₹20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

जनवरी 2026

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS-35

राजभवन शिक्षा विभाग के मिली भगत से कुलपति डॉक्टर शाही ने मगध विश्वविद्यालय को बनाया लूट का अड्डा

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट

www.shruticommunicationtrust.org

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)
Jharkhand State Office:- **Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi**
Mob.- 9431073769

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

सत्येन्द्र नाथ बोस
01 जनवरी 1894

नाना पाटेकर
01 जनवरी 1951

विद्या बालन
01 जनवरी 1978

ममता बनर्जी
05 जनवरी 1955

दीपिका पादुकोण
05 जनवरी 1986

विपाशा वसु
07 जनवरी 1979

ए.आर. रहमान
08 जनवरी 1966

फराह खान
09 जनवरी 1965

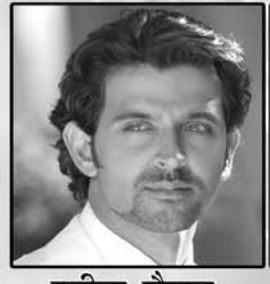

हृतीक रौशन
10 जनवरी 1974

राहुल द्रविड
11 जनवरी 1973

स्वामी विवेकानन्द
12 जनवरी 1863

प्रियंका गांधी
12 जनवरी 1972

राकेश शर्मा
13 जनवरी 1963

मायावती
15 जनवरी 1956

जावेद अख्तर
17 जनवरी 1945

सुभाष चन्द्र बोस
23 जनवरी 1897

स्व. बाल ठाकरे
23 जनवरी 1926

बॉबी दिओल
27 जनवरी 1967

लाला लाजपत राय
28 जनवरी 1865

प्रिति जिंटा
31 जनवरी 1975

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

‘‘ विश्वगुरू का सपना देखने वाला भारत देश में - 40 वाले डॉक्टर बनकर भारत के बीमार लोगों का ईलाज करेंगे। मन की बात करते - करते जातिगत काम की बात को महत्व देने लगे पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी। सवर्णों के बच्चे भले ही खूब पढ़ें लेकिन उनको आने वाले समय में डॉक्टर - इंजीनियर बनने का सपना देखना बंद करना पड़ेगा क्योंकि बाप बेटी बचायेगा और लड़के का बाप अपना जेनरेशन बदलने के लिए बेटी बचाने वाले बाप की बेटी से जबरन विवाह कर लेगा और कानून के पास जाने पर बेटी के बाप को जेल भी जाना पड़ेगा। ऐसा ही माहौल 21वीं सदी के अमृत काल में होने जा रहा है। हिन्दूराष्ट्र बनाइये, अंधभक्ति दिखाइये, मन की बात सुनिए लेकिन काम की बात करने पर आपको कानून का दंड झेलना पड़ सकता है। देश के भीतर गृहयुद्ध की स्थिति बन चुकी है, बस शंखनाद होना बाकी है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है की सवर्ण अपनी औकात में रहें, अन्यथा..... ’’

— — — — — —

ब्रजेश मिश्र, संपादक
8340360961, 9431073769

कभी भी हो सकता है गृहयुद्ध

बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर 2024 के चुनाव में किसी प्रकार केन्द्र में मोदी सरकार ने वापसी कर ली लेकिन आरक्षण के गंभीर मुद्दे को देश के भीतर राजनीति के लिए छोड़ते हुए यह कहा कि मेरे रहते कोई आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता। आरक्षण की समीक्षा की बात आर एस एस के प्रमुख मोहन भागवत ने कही थी लेकिन 2026 में इस प्रकार यूजीसी में आरक्षण का ऐसा घिनौना कूटनीति होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि देश का सवर्ण को बिना दोष का गुनहगार साबित किया जा सकता है, कानून बना दिया गया है। आजादी के बाद कांग्रेस और अब भाजपा ऐसे – ऐसे कानून बना रही है जिसकी वजह से भारत हिन्दू राष्ट्र बनना तो दूर हिन्दू खंड– खंड में विखंडित हो जायेगा और संघर्ष एवं आन्दोलन करने वाले को काला पानी से भी दर्दनाक दंड को सहना पड़ेगा। भले ही आप कट जाये लेकिन आपको बंटना ही होगा। धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा को अयोध्या, मथुरा एवं काशी की समस्या का समाधान के बाद अब उसको जातिगत राजनीति में सत्ता की महत्वकांक्षा साफतौर पर दिख रही है। यह विडम्बना नहीं तो और क्या है कि **‘‘बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ’’** का नारा देने वाली भाजपा यूजीसी में ऐसा कानून बना दिया कि बेटी पढ़ने के क्रम में कब इस कानून का शिकार हो जाये और इसके विरूद्ध कोई आवाज भी नहीं उठाई जा सके। सत्ता के लिए भारत देश में कब हिन्दू – मुस्लिम दंगा हो जाये उससे संसकित रहने वाला भारतीय अब कब हिन्दू में ही जातिगत दंगा होकर गृहयुद्ध का वातावरण बन जाये उसको पूरा माहौल तैयार किया जा चुका है। देश की सीमा पर अपने प्राणों की आहूति देने वाला जवान के घरवाले जातिय हिंसा का शिकार हो जायें उसकी चिंता में कहीं सीमा ही असुरक्षित न हो जाये उसको भी राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। लोकतांत्रिक देश में प्रतिभा का हनन करके विश्वगुरू बनने का सपना सिर्फ छलावा कि सिवा कुछ भी नहीं है और बाद में यह जुमला था कहकर पल्ला झाड़ लेने से भारत गृहयुद्ध से बच नहीं सकता। एक भारत–श्रेष्ठ भारत तभी बन सकता है जब देश की एकता को मजबूत करने वाला कानून हो न कि आपस में लड़ाकर एकता को ही खंडित करने वाला काला कानून बनाकर उसकी राजनीति किया जाये। किसी भी प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कूटनीति अच्छी है लेकिन उस कूटनीति से राष्ट्र का वजूद ही खतरे में आ जाये तो ऐसे राजनीति करने वाले से अवश्य बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रतियोगिता करने के बजाय ईर्ष्या करने से आप योग्य नहीं बन सकते बल्कि उसकी आग में प्रतियोगिता एर्वं ईर्ष्या करने वाला जलता रहता है। मध्यप्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा का अशोभनीय बयान पर कार्रवाई करने के बजाय अधिवक्ता अनिल मिश्रा को गिरफ्तार करके देश के सवर्णों को यह संदेश देना की 80 के आगे 20 वाले की बुनियाद कुछ नहीं है और सरकार 80 को अपने पक्ष में करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। एमपी और यूपी के मुख्यमंत्री किस प्रकार रिमोर्ट से संचालित हो रहे हैं कि उन्हें इस बात का भान ही नहीं है कि आने वाले वक्त उनको इसका भारपाई कर पाना नामुमकिन हो जायेगा। भूराबाल साफ करो एवं माय समीकरण का नारा भारत की राजनीति से लालू परिवार को इतना कमजोर बना दिया है कि विपक्ष के लायक भी नहीं बचे हैं। 80 की संख्या में भी योग्यता और संस्कार है जिसकी वजह से वह वहीं निर्णय लेते हैं जो प्रदेश एवं देशहित में हो जिसकी वजह से तोड़ने की राजनीति करने वाले के मंसूबे को पानी फेर दिया है। विदेशी अक्रांताओं के आतंक से जब सनातन संस्कृति विलुप्त नहीं हुई तो अब चंद मिनटों में एक शहर ही खबर दूसरे शहर में पहुंच जाती है वैसे में सनातन को आंख दिखाने वाले सफल नहीं हो सकते। गौ, गंगा, गायत्री की राजनीति करने वाली भाजपा ने इनके साथ किस प्रकार भेदभाव कर रही है यह साफतौर पर परिलक्षित हो रहा है। आरक्षण के साथ–साथ एक वर्ग को खलनायक तो दूसरे वर्ग के अपराध करने के बाद भी नायक बनाने के लिए कानून बना देना अच्छे दिन के हीं सुखद परिणाम है। अंधभक्ति और पद लोलुप्ता की महत्वकांक्षा ने अपने ही बच्चों के भविष्य से खेलने वाला का चरणवंदना करना देश को गृहयुद्ध में झोकना नहीं तो और क्या है। सभी सवर्ण के सांसद, विधायक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पार्टी एवं संघ के योद्धा अपनी सकरात्मक बात को मजूबती से अपने देश के प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री के पास रख नहीं सकते, लेकिन जब अपने स्वाभिवान एवं संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर खूनी संघर्ष होगा तो यह कैसे अपने ही वर्ग को संभाल पायेंगे, यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। देश के अधि वक्ताओं ने जिस प्रकार आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था उसी प्रकार लोक एवं जनप्रिय अधिवक्ता विष्णु कुमार जैन, अश्विनी उपाध्याय, अनिल कुमार मिश्रा ने आज भारत के काला कानून के विरूद्ध मोर्चा खोल रखा है। वक्त रहते काला कानून को गंभीरता से अवलोकन करते हुए भारत को गृहयुद्ध होने से रोकना होगा, अन्यथा......।

दिसम्बर 2025

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

विफलता

ब्रजेश जी,

शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की खबरें सिस्टम को झकझोर देती है लेकिन सरकार एवं प्रशासन का आंख नहीं खुलता। दिसम्बर 2025 अंक में ''**विषाक्त सिरप कांड-रघुवंशी**'' में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की दर्दनाक कहानी को पूरे तथ्यों के साथ लिखा है की किस प्रकार केन्द्र एवं राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आवाम के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे डर लगता है की ऐसे पत्रकारों को कहीं माफिया और भ्रष्ट शासन-प्रशासन इनको टारगेट न कर ले। सटीक खबर।

✦ **धर्मेन्द्र तिवारी, बिरसा चौक, राँची, झा०**

जमीन

ब्रजेश जी,

''**अपराध की प्रमुख जड़ है जमीन**'' दिसम्बर 2025 अंक का संपादकीय मुझे वर्त्तमान समय के हिसाब से काफी सटीक लगा। इस प्रकार की जानकारी एवं सरकार के समक्ष मजबूती से ऐसे विषय को रखना सकरात्मक पत्रकारिता का परिचय है। आपका संपादकीय प्रत्येक अंक में आमजनता के साथ प्रशासन और सरकार तीनों को संबोधित करके लिखा जाता है जिसका लाभ मिल सके। बिहार में बढ़ते अपराध में विवादस्पद जमीन की बड़ी भूमिका है और इसपर नियंत्रण की जानकारी भी सटीक है।

✦ **रमेश यादव, नेहालचक, बेलदारीचक, पटना**

गुरू को समर्पित

मिश्रा जी,

केवल सच, पत्रिका के दिसम्बर 2025 अंक में सिखों के बलिदान एवं राष्ट्र के प्रति योगदान को लेकर पत्रकार अमित कुमार, संजय कुमार सिन्हा, गौतम चौधरी ने अपने आलेख में युवा पीढ़ी के लिए सही संदेश दिया है। काफी लंबे समय बाद सिखों के उपर इतनी सटीक समीक्षात्मक जानकारी को पाठकों के बीच रखा गया है। आपकी पत्रिका सभी धर्म एवं समुदाय के अच्छे कार्यों को बिना भेदभाव के लोगों के बीच रखते हैं। जगमोहन सिंह गिल की खबर भी पठनीय एवं संग्रहनीय है। विशेषांक की शुभकामनाएं भी पाठकों को प्रेरित करती है। इस अंक में गुरू जी की विजय गाथा को रखने के लिए साधुवाद।

✦ **जनरल सिंह, सिटी चौक, पटनासिटी, बिहार**

विशेषांक

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका के दिसम्बर 2025 अंक में प्रकाशित सिखों के 10वे गुरू गुरू गोविन्द सिंह की जीवनी पर समीक्षात्मक खबर को विशेषांक में लिखा गया है। सनातन की रक्षा में गुरू जी एवं उनके साहेबजादों की कुर्बानी को पूरा देश याद करेगा और ऋणि रहेगा। अमित कुमार एवं अन्य लेखकों ने अपने-अपने स्तर से सच्ची और अच्छी जानकारी को पाठकों के बीच रखा है। विशेषांक के प्रकाशन के लिए पत्रिका प्रबंधन को हार्दिक बधाई की धर्म - न्याय की रक्षा करने वाले गुरू जी को आपने इसे समर्पित किया है। इस अंक में बहुत सटीक जानकारी आपकी पत्रिका ने दिया है।

✦ **त्रिलोक सिंह, करोल बाग ओपी, नई दिल्ली**

महालूट

संपादक जी,

आपकी पत्रिका केवल सच, बेबाक खबरों के लिए अलग पहचान रखती है तथा कोई भी खबर बिना किसी से डरे लिखती है। दिसम्बर 2025 अंक में प्रकाशित ''**बीएमएसआईसीएल में अरबों की लूट**'' खबर में पत्रकार शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की संयुक्त रिपोर्ट में विभाग के द्वारा महालूट की जानकारी तथ्यों के साथ रखा है और किस प्रकार एमडी निलेश रामचंद्र देवरे ने अवैध कमाई की है उसका खुलासा किया है। निडरता एवं प्रमाण के साथ खबर को लिखने की वजह से सरकार एवं प्रशासन में इसकी मजबूत पहचान है।

✦ **दिनेश पाठक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली**

शिवानी हत्याकांड

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका के दिसम्बर 2025 अंक में ''**शिवानी वर्मा हत्याकांड**'' पर पत्रकार मिथिलेश कुमार ने पूरे मामले की पड़ताल करते हुए सरकार एवं पुलिस पर कड़े सवाल उठाये हैं जो बिल्कुल सच है। अपराधी बेलगाम है और सरकार दावा करती है की प्रदेश में कानून का राज कायम है जो बिल्कुल बिहार की जनता को धोखा देने वाली बात है। बिहार में अपराधियों को अब पुलिस से डर नहीं लगता जिसकी वजह से एक के बाद एक घटना को अंजाम देने में सफल हैं और पुलिस की लापरवाही की वजह से प्रदेश की जनता खतरे में है।

✦ **प्रमोद साव, पासवान चौक, हाजीपुर, वैशाली**

अन्दर के पन्नों में

10

नगर परिषद् के काले कारनामे.....71

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 20 | अंक:- 236 | माह:- जनवरी 2026 | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन) 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

डॉ० शशि कुमार 9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संतोष कुमार यादव 8210487516

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

कुमार अनिकेत 9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-		
(ग्रा०)	:-	मुकेश कुमार	9473038020
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-		
	:-		
गया (श०)	:-		
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9162664468
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-		
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	.	
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-		
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

.....

.....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

.....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र 7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

.....

संयुक्त संपादक

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :-
खूँटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाइईबासा		

भाजपा की कैसी रणनीति!

मुख्यमंत्री नीतीश के बाद नवीन!

● **अमित कुमार**

भारतीय जनता पार्टी के युवा, कर्मठ, निष्ठावान और जुझारू नेता नितिन नवीन, जो लगातार राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा से जीत हासिल करते आ रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये गये हैं। नई दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय में नितिन नवीन की ताजपोशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इनकी निर्वाचन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं शामिल हुए और हांथ पकड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी वाली कुर्सी पर बिठाकर उन्हें मुंह मीठा कराया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने को लेकर दिये संबोधन में कहा कि, ''नितिन नवीन आज से मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं। लोगों को लगता होगा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 50 साल की छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। 25 साल से सरकार के मुखिया हैं। ये सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। आज के युवाओं की भाषा में कहें तो नितिन जी खुद मिलिनियल हैं। 45 साल के नितिन नवीन उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, जिसने बड़े आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलाव देखे हैं। उनकी पीढ़ी के लोगों ने रेडियो से एआई तक का सफर तय किया है। ऐसे में नितिन जी के पास युवा शक्ति हने के साथ-साथ संगठन में काम करने का अनुभव भी है। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा।'' वही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि, ''आज सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. आपने मुझ जैसे

एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी के इस सर्वोच्च पद तक पहुंचने का अवसर दिया है और इसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं. प्रधानमंत्री, मैं आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. क्योंकि हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं ने हमेशा दूर से देखा है कि आप राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया था, उस वक्त मैं राष्ट्रीय महासचिव था और मैंने सद्भावना मिशन कार्यक्रम के दौरान आपको प्रत्येक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हुए देखा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद, जब आपने अपने ग्रीन रूम में हमसे बात की तो आपने बड़ी भावुकता से समझाया कि गुजरात से इतने सारे लोग क्यों आए थे... उस दिन मुझे समझ आया कि एक व्यक्ति तभी महान बनता है, जब वह जनता की भावनाओं से जुड़ता है।'

गौरतलब है कि नितिन नवीन को बीजेपी का पहले कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक पत्र में बताया गया था कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पत्र के अनुसार नितिन नवीन की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। वो बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वही पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर नितिन नवीन को बधाई दी थी और लिखा कि एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने लिखा कि 'वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं, जिनके पास संगठन का अच्छा-खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है, साथ ही जनआकांक्षाओं को पूरा करने के

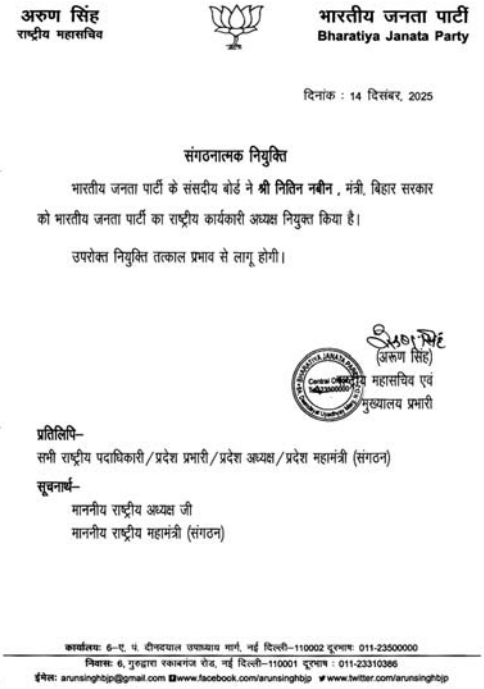

अरुण सिंह
राष्ट्रीय महासचिव

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

दिनांक : 14 दिसंबर, 2025

संगठनात्मक नियुक्ति

भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने **श्री नितिन नबीन**, मंत्री, बिहार सरकार को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।

उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(अरुण सिंह)
राष्ट्रीय महासचिव एवं
मुख्यालय प्रभारी

प्रतिलिपि–
सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी/प्रदेश प्रभारी/प्रदेश अध्यक्ष/प्रदेश महामंत्री (संगठन)

सूचनार्थ–
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
माननीय राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन)

कार्यालय: 6-ए, पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 दूरभाष: 011-23500000
निवास: 6, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 011-23310386
ईमेल: arunsinghbjp@gmail.com www.facebook.com/arunsinghbjp www.twitter.com/arunsinghbjp

लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। मोदी ने लिखा 'वे अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई।'

बताते चले कि बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जन्म मई 1980 में रांची, झारखंड में हुआ। नितिन नवीन ने साल 1996 में पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल से मैट्रिक और 1998 में दिल्ली के सीएसकेएम पब्लिक स्कूल से इंटर की पढ़ाई पूरी की है। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाये जाने के बाद नितिन नवीन ने अपना इस्तिफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दिया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने से पहले वह पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री बनाये गये थे। नितिन के पास सत्ता और संगठन दोनों को चलाने का अनुभव है। पार्टी ने नितिन नवीन

को बड़ी जिम्मेदारी सौंप एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। 45 वर्षीय नितिन नवीन के बारे में कयास लगाये जा रहे थे कि बहुत जल्द उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें स्थायी तौर पर भी पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है।

सनद् रहे कि नितिन नवीन ने साल 2006 में राजनीति की शुरुआत की थी। मान सकते हैं कि उन्हें यह विरासत में मिली। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा शुरुआती दौर में कई बार बीजेपी से विधायक रहे थे और पिता के निधन के बाद नितिन नवीन उस सीट से लगातार जीत रहे हैं। नितिन के पिता नवीन किशोर भी भाजपा के कद्दावर नेता थे। वे पार्टी के टिकट पर कई बार विधानसभा चुनाव चुने गए थे। नवीन के निधन के बाद नितिन राजनीति में सक्रिय हुए। नितिन नवीन साल 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। साल 2010 से 2025 तक वो लगातार 5 बार बांकीपुर सीट से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। वे बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहे। साथ ही वे छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट, संगठन विस्तार और चुनावी तालमेल पर फोकस कर पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी। कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन 2016 में बिहार भाजपा युवा मोर्चा की कमान संभाल चुके हैं। 2021 में उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया था। 2024 में बिहार सरकार में उन्हें शहरी विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। हाल ही में बिहार चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के बाद नीतीश सरकार में उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाया गया था।

गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पदभार संभाला। भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार के मंत्री और तेज-तर्रार नेता नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ही लोग मिलने वाले वेतन और भत्तों के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी का अध्यक्ष या कोई भी और ओहदा सरकारी पद नहीं है। इसलिए सरकार की तरफ से उन्हें न तो कोई सैलरी मिलेगी और न ही किसी और तरह का भत्ता। यह पद पार्टी संगठन से जुड़ा है। इस पद से जुड़ा खर्च सरकार नहीं बल्कि पार्टी खुद वहन करती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पार्टी की ओर से अपने अध्यक्ष को हर महीने लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मानदेय देती है। यह राशि पार्टी के आंतरिक फंड से दी जाती है। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पार्टी की ओर से नहीं दी गई है। ध्यान रहे कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष

INDIAN EXPRESS

Bharatiya Janata Party launched

Vajpayee elected president

Ordinance bans strikes in Assam

Members 'free' to attend shakhas

Zail Singh asked to resign

Assam stir intensified

Shah panel SSP superseded

किसी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से कम नहीं होता है। नितिन नवीन को भी दिल्ली में आधिकारिक आवास, कार्यालय और सहयोगी स्टाफ की सुविधा मिलेगी। इस टीम में निजी सचिव, राजनीतिक सलाहकार, मीडिया टीम और सोशल मीडिया मैनेजर शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त नितिन नवीन की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा समीक्षा के बाद उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी। पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को Z कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त है। पार्टी से जुड़े सभी कार्यक्रमों और यात्राओं का खर्च पार्टी फंड से दिया जाता है। इसमें हवाई यात्रा, सड़क मार्ग से सफर, ड्राइवर और लग्जरी वाहन जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। मंत्री पद पर बने रहते हुए कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं तो उन्हें मंत्री पद से जुड़ी सभी सरकारी सुविधाएं और भत्ते अलग से मिलते रहेंगे।

बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन को नियुक्त कर मोदी-शाह की जोड़ी ने एक बार फिर सियासी पंडितों कौ चौंका दिया है। भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल तमाम दिग्गजों को एक किनारे करते हुए पार्टी संसदीय बोर्ड ने जिस तरह से 45 साल के नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया, उससे साफ है कि संघ और भाजपा अब तीसरी पीढ़ी के नेताओं के हाथों में पार्टी की कमान देने के लिए आगे बढ़ चुकी है। दिगर बात है कि नए

कार्यकारी अध्यक्ष के एलान से 48 घंटे पहले अंडमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत और गृहमंत्री अमित शाह का एक साथ होना इस बात का साफ संदेश था कि नितिन नवीन के नाम पर संघ की सहमति ली गई थी। संयोग यह भी है कि नितिन नवीन का जन्म उसी साल हुआ था, जिस साल भाजपा का गठन यानी साल 1980 । ऐसे में नितिन नवीन की नियुक्ति से यह संदेश साफ है कि पार्टी में जेनरेशन नेक्स्ट का दौर अब शुरू हो चुका है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अब 2047 को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। यहीं कारण है कि मध्यप्रदेश में डॉ० मोहन यादव, हरियाणा में नायाब सिंह सैनी, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय जैसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा अब नेक्स्ट जेनरेशन की ओर आगे बढ़ चुकी है। वही नितिन नवीन की नियुक्ति से भाजपा ने जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं और भाजपा जिसे नब्बे के दशक में बनियों की पार्टी कहा जाता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान नितिन नवीन सिन्हा के हाथों में होना, एक नयी कह सकते है। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों

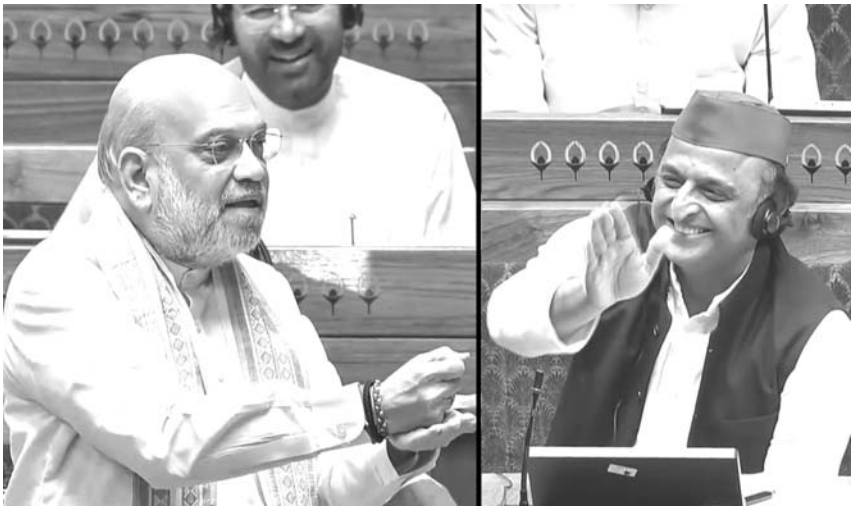

में जब 90 के दशक में जातिवाद अपने चरम पर था, तब भाजपा को अगड़ी जातियों की पार्टी के तौर पर देखा जाता था और इस कालखंड में अगड़ी जातियां भाजपा से खूब जुड़ी और इन्हें पार्टी के कोर वोट बैंक के तौर पर देखा गया। नितिन नवीन उस बिहार से आते है जहां पर कायस्थ समाज की आबादी एक प्रतिशत से भी कम है, लेकिन पार्टी ने अब उन्हें राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर लाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग से आते है तब कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन सिन्हा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है। 45 वर्ष के नितिन नवीन का यह प्रमोशन युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने का संकेत है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या वे अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं? नितिन नवीन का बीजेपी में सफर संघर्षपूर्ण और तेजी से ऊपर उठने वाला रहा है। पार्टी ने उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं जो उनकी संगठनात्मक क्षमता और चुनावी सफलता का प्रमाण हैं। वे दो बार राष्ट्रीय महामंत्री (युवा मोर्चा) रह चुके हैं, जहां उन्होंने युवाओं को पार्टी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। बिहार में वे प्रदेश अध्यक्ष (युवा मोर्चा) के रूप में सक्रिय रहे, जिससे राज्य स्तर पर बीजेपी की युवा शाखा मजबूत हुई। इसके अतिरिक्त वे सिक्किम के प्रभारी और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके हैं जहां उन्होंने पूर्वोत्तर और मध्य भारत में पार्टी का विस्तार किया।

गौरतलब है जब पुरानी घटनाओं को याद करेंगे तो नितिन नवीन का पीएम मोदी के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में पता चलेगा। ज्ञात हो कि जिस तस्वीर के विरोध में नीतीश कुमार ने एक बार डिनर का कार्यक्रम रद्द कर दिया था, अखबारों में वो तस्वीर नितिन नवीन और संजीव चौरसिया ने छपवाई थी! इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में कोई चर्चा नहीं थी, तब से ही नितिन नवीन का मोदी की तरफ झुकाव था। दरअसल यह घटना साल 2010 की है जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना आए थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अखबारों में छपे एक विज्ञापन पर अपनी नाराजगी जताई थी। इस विज्ञापन में दिखाया गया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हाथ पकड़े खड़े हैं। इसमें लिखा गया था कि कैसे बाढ़ जैसी आपदा के दौरान गुजरात सरकार ने बिहार की मदद की। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था ये विज्ञापन बिना उनकी अनुमति के छापा गया है। उस वक्त इस बात की भी काफी चर्चा थी कि विज्ञापन से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के साथ डिनर का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। नितिन नवीन को बीजेपी का वर्किंग प्रेसिडेंट क्यों बनाया, यह तुरंत पक्के तौर पर बता पाना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनपर भरोसा करता है।

विडम्बना है कि बीजेपी में लंबे समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर फैसला नहीं हो पाया था। इस मुद्दे की चर्चा राजनीतिक हलकों के अलावा संसद में भी होती रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद में आरोप लगाया था कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई है। उस वक्त इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव के आरोपों के जवाब में कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, पारिवारिक पार्टी नहीं है, इसलिए देरी होती है। बीजेपी लंबे समय से जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा रही है और इसलिए इस मुद्दे पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। यह एक आश्चर्य भरा फैसला है। करीब तीन साल से जेपी नड्डा को एक्टेंशन दिया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे पर सवालों से बचने के लिए बीजेपी ने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन

यह कदम सवालों को और ज्यादा बढ़ा रहा था लोगों में यह सवाल भी था कि क्या बीजेपी और आरएसएस में कोई मतभेद है? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं है, जो पूर्णकालिक अध्यक्ष न बनाकर अभी कार्यकारी अध्यक्ष का नाम सामने आया? बता दें कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष पद का काम जो भी नेता संभालेगा, उसके पास राष्ट्रीय स्तर पर एक विजन होना चाहिए, उसे देश के अलग-अलग इलाकों में लोगों के साथ बैठकें करनी होती हैं। हालांकि ऐसा कई बार देखा जाता है कि किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी ऐसे शख्स को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपता है जिसके साथ मिलकर काम को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके और नितिन नवीन ने इसे साबित किया है, जिस कारण कार्यकारिणी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल चुकी है। लेकिन बीजेपी का यह फैसला क्या राजनीतिक चर्चा को विराम देगा या विपक्ष इस मुद्दे पर नए सवाल खड़े करेगा, यह देखना अभी बाकी है। वही पार्टी संविधान और नियम में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका का जिक्र नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो नए अध्यक्ष के चुने जाने तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएंगे या फिर उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया जा सकता है?

विदित हो कि साल 2019 के बाद से बीजेपी में पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की एक परंपरा शुरू हुई। नितिन नवीन की नियुक्ति बीजेपी की उसी परंपरा से जुड़ती है जहां राष्ट्रीय महासचिव या कार्यकारी अध्यक्ष जैसे पदों पर रहते हुए कई नेता बाद में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। पार्टी के इतिहास में यह एक साफ पैटर्न दिखता है, जहां आरएसएस पृष्ठभूमि वाले या संगठन प्रबंधक नेता इस 'ट्रांजिशन' से गुजरते हैं। प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो अमित शाह की तो वह 2010 में राष्ट्रीय महासचिव (संगठन)

बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने 2014 लोकसभा चुनावों में पार्टी को 282 सीटें दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उसी वर्ष जुलाई 2014 में वे पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और 2020 तक इस पद पर रहे। शाह का कार्यकाल बीजेपी का 'गोल्डन पीरियड' माना जाता है जब पार्टी ने 2019 में 303 सीटें जीतीं। यह परंपरा का बेहतरीन उदाहरण इस मायने में भी है कि जहां महासचिव से अध्यक्ष बनने का सफर सिर्फ चार साल का रहा। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सफर भी इसी परंपरा का हिस्सा है। वे 2010 में हिमाचल प्रदेश सरकार से मंत्री पद छोड़कर राष्ट्रीय महासचिव बने। 2014-2019 तक वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन 2019 में अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद वे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष (वर्किंग प्रेसिडेंट) नियुक्त हुए। जनवरी 2020 में वे पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और आज तक इस पद पर हैं। नड्डा की नियुक्ति ने बीजेपी को महामारी काल में स्थिरता दी और 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत में उनकी भूमिका सराहनीय रही। उनका ट्रांजिशन महासचिव से कार्यकारी अध्यक्ष होते हुए पूर्ण अध्यक्ष पद तक पहुंचा, जो नितिन नवीन के लिए एक मॉडल हो सकता है। जानकारों की नजर में ये उदाहरण बीजेपी की आंतरिक प्रणाली को दर्शाता है, जहां राष्ट्रीय महासचिव पद को 'अध्यक्ष पद का इनक्यूबेटर' माना जाता है। जानकारी के अनुसार, 1980 में बीजेपी की

स्थापना के बाद से 11 राष्ट्रीय अध्यक्षों में से कम से कम चार (अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और लालकृष्ण आडवाणी) ने महासचिव या समकक्ष पद संभाला था। हालांकि, यह हमेशा गारंटीड नहीं होता, जैसे नितिन गडकरी (2009-2013 अध्यक्ष) सीधे संगठन से आए थे और वह भी बिना महासचिव बने हुए। फिर भी, आरएसएस प्रभावित नेताओं के लिए यह ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत कहा जा सकता है। नितिन नवीन के मामले में राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह नियुक्ति 2029 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले उनकी टेस्टिंग हो सकती है।

ज्ञात हो कि कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौरपर पहले नितिन नवीन बनाये गये, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हालांकि जेपी नड्डा भी अध्यक्ष बनने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। 2019 में जब बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बने तब पार्टी ने पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में राष्ट्रीय अध्यक्ष औपचारिक रूप से सबसे बड़ा पद है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष अस्थायी, अनाधिकारिक और एक ऐसा पद है, जिसका पार्टी के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि जब कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी ही है तो पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नियुक्त किया है? इसका कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं है लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने संविधान के हिसाब से होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को आम सहमति और निर्विरोध रूप से करना चाहती है और ऐसा ही हुआ भी। बीजेपी ने जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। पार्टी में इसकी एक औपचारिक प्रक्रिया है। ऐसे तो कोई चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन नामांकन तिथि, चुनाव तिथि ये औपचारिक प्रक्रियाएं हैं, पार्टी को इन्हें करना है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर बीजेपी ने ये साफ कर दिया था कि नितिन नवीन ही अगले अध्यक्ष होंगे और हुआ भी ऐसा। पार्टी के भीतर से इस पद के लिए किसी ने भी दावेदारी पेश नहीं की।

मतलब नितिन

निर्विरोध रहे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति चुनाव से होती है जो आमतौर पर गुप्त बैलेट के जरिए होता है। हालांकि आमतौर पर पार्टी अध्यक्ष आम सहमति से निर्विरोध ही चुने जाते रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मतदान करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम आधे राज्यों में पार्टी की जिला, मंडल और राज्य स्तरीय पदों के लिए नियुक्तियां पूरी हो जानी चाहिए। बीजेपी ने देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में संगठन के पदों के लिए चुनाव पूरे कर लिए हैं। पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है और अधिकतम एक व्यक्ति लगातार दो कार्यकाल पूरे कर सकता है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। आम सहमति से लेकर आंतरिक चुनाव इसका मुख्य कारण होते हैं। जेपी नड्डा जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और फिर जनवरी 2020 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब नितिन नवीन को भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया।

बहरहाल, 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक चुने जाने वाले नितिन नवीन पांच बार से लगातार विधायक हैं और बिहार से बीजेपी के पहले अध्यक्ष हैं। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल तीन साल पहले ही समाप्त हो गया था और उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था। 45 साल के नितिन नवीन का कार्यकारी अध्यक्ष बन जाना जरूर कई लोगों को हैरान कर रहा है लेकिन विश्लेषक इससे हैरान नहीं है। बिहार चुनावों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन से दो घंटे मुलाकात की थी। अगर पीछे की कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो नितिन नवीन का नाम बहुत हैरान नहीं करता है। नितिन नवीन पार्टी के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के प्रभारी थे और बीजेपी ने

यह चुनाव भारी बहुमत से जीता था। यानी नितिन नवीन अपनी संगठनात्मक क्षमता पहले ही साबित कर चुके हैं। किन्तु सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नितिन नवीन की नियुक्ति के पीछे कोई खास वजह या पार्टी की कोई खास रणनीति है? विश्लेषक मान रहे हैं कि पार्टी में ये बदलाव का दौर है और ये समय की जरूरत के हिसाब से उठाया गया कदम है। पार्टी जनरेशन चेंज यानी पीढ़ीगत बदलाव से गुजर रही है। पार्टी में पुरानी पीढ़ी के नेताओं की जगह नए नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में पुराने नेताओं को हटाना और नए चेहरों को लाना पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा है और नितिन नवीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना इस कड़ी में अगला कदम है। पार्टी नए नेतृत्व को आगे लाना चाहती है और ये नियुक्ति भी उसी दिशा में है। नितिन नवीन युवा नेता हैं। बीजेपी ने इससे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम बनाकर, राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल को और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया। पार्टी ऐसा करती रही है। बीजेपी में ऐसे नेताओं को आगे लाया जा रहा है जो किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी या अमित शाह के लिए चुनौती पेश ना करें। नितिन नवीन की नियुक्ति हैरान इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें अमित शाह की सहूलियत के हिसाब से बनाया गया है। वो पार्टी के ऐसे कोई मजबूत नेता नहीं है, जिनसे अमित शाह को किसी तरह की चुनौती मिल सके। बीजेपी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को इस तरह बना रही है कि नरेन्द्र मोदी के बाद अमित शाह की ही जगह बने। किसी भी ऐसे नेता को मजबूत पद पर नहीं लाया जा रहा है, जो आगे चलकर किसी भी तरह की चुनौती पेश कर पाए। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करीबी रिश्ता रहा है और आरएसएस को पार्टी का वैचारिक अभिभावक माना जाता है।

विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि नितिन नवीन का नाम उन चुनिंदा लोगों में रहा होगा जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। संघ, बीजेपी को कोई एक नाम नहीं देता है जो चार-पांच नाम सुझाए होंगे, उनमें नितिन नवीन का नाम रहा होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सहमति के बाद उन्हें पहले कार्यकारी अध्यक्ष और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए शिवराज सिंह चौहान, धर्मेन्द्र प्रधान, भूपेन्द्र यादव, सुनील बंसल सहित और पार्टी के कई अन्य नेताओं का नाम भी मीडिया रिपोर्टों में आ रहा था। विश्लेषक मान रहे हैं कि जब जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तब भी कई नेताओं के नाम चर्चा में थे और उस समय भी उनकी नियुक्ति ने हैरान किया था। बहुत से लोगों को नितिन नवीन अभी बड़े नेता नहीं लग रहे हैं। उनका नाम नया लग रहा है, लेकिन साल दो साल बाद वो भी ऐसे ही बड़े नेता लगने लगेंगे जैसे जेपी नड्डा। हालांकि, विश्लेषक इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि बीजेपी में इस समय सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इर्द-गिर्द ही केंद्रित है और पार्टी के सभी निर्णयों पर इन दो शीर्ष नेताओं की छाप साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नितिन नवीन की नियुक्ति से खुश ही होंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि पार्टी में अमित शाह के लिए कोई चुनौती खड़ी हो। नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिशा निर्देशन में ही काम करेंगे और उनके लिए पार्टी के भीतर कभी चुनौती नहीं बनेंगे।

विदित हो कि इसी वर्ष पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं। उसके बाद साल 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव हैं। हालांकि विश्लेषक ये मान रहे हैं कि पार्टी ने

कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति आगामी चुनावों को देखते हुए नहीं की है। नितिन नवीन ना ही पश्चिम बंगाल का चुनाव जिता सकते हैं और ना ही उत्तर प्रदेश का। पार्टी में बड़े बॉस बैठे हुए हैं, जो रूटीन काम हैं, संगठनात्मक दृष्टि से उन्हें करने के लिए नितिन नवीन को लाया गया है। अब नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये गये हैं और 1980 में पार्टी के गठन के बाद से कायस्थ जाति से आने वाले पहले अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन कायस्थ हैं और बिहार से आते हैं, जहां कायस्थ एक प्रतिशत से भी कम हैं, ऐसे में उनका कोई बहुत बड़ा जमीनी राजनीतिक आधार नहीं है, लेकिन पार्टी को लग रहा है कि वो संगठन को सही से संभाल लेंगे। साथ ही वो पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं और 52 साल की उम्र में पार्टी की कमान संभालने वाले नितिन गडकरी का सबसे युवा अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जे.पी. नड्डा पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं।

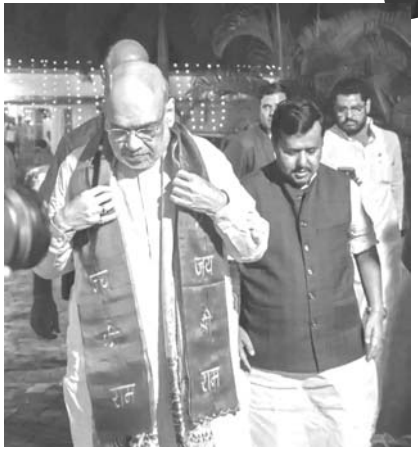

बहरहाल, बीजेपी ने देशभर में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, मगर ये पूरी प्रक्रिया इतनी धीमी गति से चलती रही कि लगभग डेढ़ साल बाद भी पार्टी के पास न तो सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष था और न ही राष्ट्रीय स्तर पर। आखिर में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सांसद पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया और उसी दिन शाम को बिहार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया।

इसके साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जयसवाल की जगह संजय सरावगी को बना दिया गया। अंतत: सारे बड़े नामों पर जारी अटकलें थम गई और सभी राजनीतिक विश्लेषकों को बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाया। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना पर कहा जा रहा था कि, हो सकता है कि ये प्रोबेशन पीरियड हो। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि राज्य स्तर पर भी जब हम लीडरशिप को देखते थे तो उनकी गिनती छठे या सातवें नंबर पर होती थी। हालांकि नितिन नवीन को राज्य स्तर पर जिम्मेदारियां देने की अटकलें लगाई जा रही थीं। इसके पीछे की वजहों के बारे में कुछ राजनीतिक घटनाओं पर गौर करे तो देख पायेंगे कि यह सब कैसे कुछ हुआ।

ज्ञात हो कि छठ पर्व के दौरान जब अमित शाह पटना आए तो नितिन नवीन के घर गए। ऐसा माना गया कि हो सकता है राज्य में चुनाव के बाद नितिन नवीन का कद बढ़े या डिप्टी सीएम का पद मिले। दूसरी घटना तब हुई जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान बिहार गए हुए थे। प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारे नेता पटना एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने गए थे। पीएम मोदी शुरुआत के मंत्रियों से मिलकर सीधे नितिन नवीन के पास रुकते हैं। यह बहुत सरप्राइजिंग था। वह उनके पास करीब डेढ़ मिनट रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। तीसरी घटना गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह की है। इसका सारा आयोजन नितिन नवीन देख रहे थे। चौथा ये कि अप्रैल 2025 में मधुबनी में हुई एक रैली को ऑर्गेनाइज करने में नितिन नवीन का बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा पार्टी के फंडिंग में उनकी एक अहम भूमिका रही है। कमोबेश और भी लोग हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिलीं, लेकिन इतना संकेत नहीं था कि नितिन नवीन को बनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मान कर चल रहे थे कि हो सकता है, इनको राज्य का इंचार्ज बनाया जाए या फिर डिप्टी सीएम बनाया जाए। जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, सभी हैरान थे। नितिन नवीन की नियुक्ति के बाद उनकी कई सारी खूबियां गिनाई गईं, जैसे कि वह युवा हैं, अच्छे संगठनकर्ता हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे विवादों में नहीं हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मात्र नितिन नवीन

ही इन सारी शर्तों को पूरा कर रहे हों, बहुत सारे नाम पहले से चल रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल जैसे नेताओं के नाम चल रहे थे। अलग-अलग समय पर अलग-अलग नाम आते रहे, इन नेताओं की राष्ट्रीय स्तर पर छवि और पहचान है। आखिर इन सबको छोड़कर प्रदेश के एक विधायक और मंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की क्या वजह रही होगी? चूकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के किसी भी फैसले का अनुमान नहीं लगा सकते, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम हो या राजस्थान और दिल्ली के। बीजेपी के अध्यक्ष के मामले में भी यही हुआ। नितिन नवीन का नाम बहुत ही आश्चर्य करने वाला था, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का कारण को समझे तो एक जो कारण कहा जा रहा है, वह ये कि नई पीढ़ी को आगे किया जा रहा है। नितिन नवीन 45 साल के हैं। नितिन गडकरी के बाद ये दूसरे सबसे युवा अध्यक्ष होंगे, लेकिन ये अकेले ऐसे नेता तो नहीं होंगे। 45 से 50 की उम्र के बीच ऐसे कई नेता होंगे जो शायद राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा अनुभवी होंगे। इन्हें क्यों बनाया गया इसका जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से ही मांगा जा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर इनकी देखी गई है कि ये कुछ ऐसे लोगों को बनाते हैं जो पहले से राष्ट्रीय स्तर पर बहुत स्टेब्लिश्ड नहीं है। जिनका राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो जमीन से जुड़े हैं, जिनके बारे में लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं या फिर हम दूसरे तरीके से इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि वे ऐसे लोगों को नहीं बनाना चाहते जिनसे उन्हें खतरा हो या उनके फैसलों को चैलेंज कर सकते हों या फिर उनकी सोच को और वे जिस तरीके से पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं।

गौरतलब है कि किसी भी पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर अंदरूनी राजनीति होती है, खींचतान होती है, कैंप होता है। बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि वो कैंप बनाना संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हिसाब से सारी पार्टी चलती है। जब आम चुनाव हुआ तो ये बात जरूर उठी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपनी भूमिका को थोड़ा और मुखर या प्रभावी करना चाहता है। ये भी कहा गया कि एक खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से इतनी आसानी से कोई नहीं बन पा रहा है। अब जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तो क्या ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इसमें ज्यादा चली है? तो कह सकते हैं कि ये उनके 'बिहार पावर ट्रांसफर प्लान' का भी पार्ट हो सकता है, क्योंकि बिहार में आप देखेंगे कि एक मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, नित्यानंद राय. .. इस तरह के नामों के बीच कड़ा कॉम्पिटीशन होता हुआ दिखता है। यहां से एक ऐसा व्यक्ति नितिन नवीन, जो अभी तक सबको चाचा-भइया कहा करते थे, पैर छूकर प्रणाम करते थे। वो अचानक सबसे ऊपर हो जाते हैं। बिहार में जब पावर ट्रांसफर का समय आता है तो नितिन नवीन की ऐसी छवि है कि उनकी जेडीयू में भी स्वीकार्यता बहुत है, संगठन में भी है। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के पीछे दो और कारण हो सकते हैं। कहीं न कहीं नितिन नवीन टॉप लीडरशिप की पसंद थे। उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने जाति राजनीति को साध लिया है। अपर कास्ट कायस्थ की आबादी एक फीसदी से भी कम है। बीजेपी का जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वहां नितिन नवीन फिट बैठते और दूसरा ये कि वह बड़े बिहार प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी को अगला मुख्यमंत्री मिल गया हो। दिगर बात है कि जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो यह कहा जा रहा है कि ये कॉडर बेस्ड पार्टी ही कर सकती है। जहां पर किसी फैसले के पीछे पूरा कॉडर बिना सोचे सपोर्ट करे कि ये किस जाति के हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को जब अध्यक्ष बनाया गया तो यह कहा गया कि ये समाजवादी पार्टी के पीडीए के कास्ट कॉम्बिनेशन की काट हैं। तो ये दोनों चीजें साथ में चलती हुई तो नहीं दिखतीं? बीजेपी को भले ही कॉडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, लेकिन वह कभी भी जाति को नजरअंदाज नहीं करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति राजनीति बहुत हावी है। पंकज चौधरी ओबीसी लीडर हैं। 2024 के

लोकसभा चुनाव में वहां का रिजल्ट बीजेपी ने देखा है, तो उस हिसाब से उन्होंने ऐसा नेता चुना है। नितिन नवीन को जिम्मेदारी देना ये दिखाता है कि बीजेपी जाति को नजरअंदाज करती है। बिहार में हाल ही में चुनाव हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात थी, इसलिए शायद वहां पर जाति को बहुत महत्व नहीं दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, वहां जरूर जाति को महत्व दिया गया। बीजेपी जब अपने कंफर्ट जोन में होती है तो वह इस तरह के प्रयोग करती है। केंद्र जब बहुत मजबूत हो जाता है तो राज्य में किसी भी प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। वही राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी लीडरशिप अपने पसंदीदा व्यक्ति को ही जिम्मेदारी दे रही है। इनमें भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, रेखा गुप्ता उदाहरण दिये जा सकते हैं। इन लोगों ने ऐसा कोई काम अभी तक नहीं किया है, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी हो या अपने आप को साबित किया हो। बीजेपी लीडिरशिप इन लोगों पर इसलिए दांव नहीं लगा रही है कि इन नेताओं में पोटेंशियल दिख रहा है या इन्हें ग्रूम करना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये रबर स्टांप लगा रहे हैं। नितिन नवीन के लिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वह रबर स्टांप ही दिख रहा है और वो जानते हैं कि वो रबर स्टैंप लगा रहे हैं। बीजेपी तर्क देती है कि अगर नई पीढ़ी के नेताओं को वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में लाकर ग्रूम नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी के नेता कैसे तैयार होंगे, रणनीतिक तौर ये सही भी लगता है? नई पीढ़ी को हमेशा तैयार करना चाहिए और हर पार्टी को ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या ये सच में नई पीढ़ी के नेता तैयार कर रहे हैं? इन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, इनमें से कौन ऐसा लग रहा जो पार्टी को आगे ले जा सकता है या जो राज्य में अपनी पार्टी को बढ़ा सकता है। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है तो धर्मेंद्र प्रधान भी तो अगली पीढ़ी हैं, तो उन्हें क्यों नहीं ग्रूम किया जा रहा? नितिन नवीन को ही क्यों चुना गया? ऐसे कई नेता होंगे। कहीं न कहीं इनकी अभी तक की पसंद देखकर लगता है कि ये ऐसे लोगों को लेना चाहते हैं जो इनके लिए खतरा न बनें, जो इनकी बात न टाले और जो इनके साथ मिलकर चले।

लब्बोलुआब है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बीच काम को लेकर अच्छे संबंध हैं, लेकिन दोनों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद भी रही है, क्योंकि दोनों एक ही इलाके से आते हैं। ऐसे में जब पंकज चौधरी की नियुक्ति होती है और वह कार्यकाल संभालते वक्त योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हैं तो ऐसे में क्या ये केंद्र की तरफ से उठाया गया ऐसा कदम है जो योगी आदित्यनाथ को असहज कर सकता है या इसमें ये संदेश है कि 2027 में चुनाव है, सबको साथ-साथ चलना है? बीजेपी इंटर्नल मैसेजिंग देने में माहिर है। एक बाहरी राजनीति चलती है और एक अंदरूनी। योगी आदित्यनाथ से किसे खतरा है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वे राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य के बहुत तेजी से उभरते हुए नेता हैं। पंकज चौधरी को लाकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का स्टेचर उससे बहुत बड़ा है। इसके साथ ही एक बात और यह भी है कि बीजेपी हमेशा चुनाव की तैयारी में होती है। वह अगला चुनाव देखकर काम करती है, लेकिन उसे उत्तर प्रदेश के मामले में योगी आदित्यनाथ पर ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बहुत लोकप्रिय हैं। आज की तारीख में वो उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं और 2024 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिस तरह का रिजल्ट मिला है, उससे थोड़ा झटका लगा होगा और ये भी समझ में आया होगा कि अगर योगी आदित्यनाथ चाहें तो वो टॉप लीडरशिप को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए उन्हें और

पंकज चौधरी को ध्यान से आगे बढ़ना होगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि इस समय योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के संगठन में, वोटर्स पर और ब्यूरोक्रेसी पर जो पकड़ है, वह बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में आप उन्हें नाराज करके चुनाव नहीं जीत सकते। आपको उनके नाम पर ही लड़ना होगा। अगर बीजेपी लीडरशिप सकारात्मक तौर पर पंकज चौधरी के नाम पर एक्सपेरिमेंट कर रही है तो सही है, लेकिन अगर वो योगी आदित्यनाथ को असहज करने की नियत से कर रही है तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ पाएगी।

बहरहाल, बीजेपी के लिए उसके नए अध्यक्ष का पद काफी अहम माना जाता है। खासकर इसी साल 2026 में पश्चिम बंगाल और उसके बाद अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए, यह जिम्मेदारी काफी बड़ी होने वाली है। बीजेपी में कभी किसी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हुई है। पार्टी की कोशिश ये होती है कि बीजेपी और संघ के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और पार्टी की जरूरत को ध्यान में रखकर अध्यक्ष का चयन किया जाता है। जब नितिन गडगरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनकी भी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका नहीं थी। अब तो बीजेपी भविष्य के लिए अपना नेतृत्व तैयार कर रही है, जिसमें कांग्रेस काफी पीछे है। हालाँकि नितिन गडकरी को आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) का करीबी माना जाता है, जबकि नितिन नवीन की संघ से कोई दूरी भले ही न हो, लेकिन उन्हें संघ का करीबी भी नहीं समझा जाता है। नितिन गडकरी का दौर बीजेपी में आरएसएस के करीबियों का दौर था। अब का युग संघ के करीबी का युग नहीं है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी का युग आ गया है। माना जाता है कि नितिन नवीन अपने सियासी करियर में कभी किसी विवाद से नहीं जुड़े हैं और इसलिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन पर भरोसा दिखाया है। नितिन नवीन को नरेंद्र मोदी के करीबी के तौर पर देखा जा सकता है। नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिखा दिया है कि पार्टी के मामले में वो आरएसएस के मुकाबले अपर हैंड रखते हैं। एक खास बात यह भी रही की बीजेपी ने नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारिणी अध्यक्ष उस दिन चुना था, जिस दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक रैली की थी। इसमें कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। बिहार की बात करें तो इस इलाके में खरमास का महीना शुभ नहीं माना जाता है हालाँकि इसका बीजेपी के फैसले से कितना संबंध है यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी 'हेडलाइन मैनेजमेंट' में माहिर है। अब हर जगह यही खबर चल रही है

कि नितिन नवीन कौन हैं? नया चेहरा पेश कर लोगों को और ज्यादा चौंकाया गया है और लोग उनके बारे में जानने के लिए ज्यादा ही उत्सुक हैं। कांग्रेस की रैली की खबर कितनी बड़ी बनती, ये तो पता नहीं लेकिन नितिन नवीन हेडलाइन बन गए। हालाँकि जानकार नितिन नवीन को प्रेसिडेंट बनाए जाने को अलग तरीके से भी देख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बीजेपी बहुत दूर की सोचती है, वो समय गँवाना नहीं चाहती। उसके सामने अभी सवाल है कि नीतीश के बाद बिहार में कौन? ऐसी बात कोई सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा अभी पार्टी में आप बहुत सारे

फेरबदल देखेंगे, तो इस लिहाज से एक कायस्थ को अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि वो बीजेपी के पक्के वोटर हैं और अक्सर सवाल उठाते रहे हैं कि क्या कायस्थ केवल वोट देने के लिए हैं? अब चूकि बीजेपी ने नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारिणी से स्थायी अध्यक्ष बना दिया है, तो उनके सामने चुनौतियाँ कम नहीं हैं। खासकर ऐसे समय जब बीजेपी कई मोर्चों पर उलझी हुई है, जिनमें विपक्ष के आरोप और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनाव सामने हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि कई नेताओं से वो काफी जूनियर हैं। जहाँ तक बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की बात है, तो वह आरएसएस के भरोसेमंद थे और उम्र के लिहाज से भी बीजेपी के कई नेताओं से काफी सीनियर थे, जबकि नितिन नवीन बिहार की राजनीति में ही सक्रिय रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका तालमेल भी काफी मायने रखेगा।

दिगर बात है कि, भाजपा अब तक बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पायी थी, ऐसे में भविष्य के मुख्यमंत्री का दाव नितिन नवीन पर लगा सकती है! ये बस कयास है किन्तु राजनीतिक गलियारे में ये गूंज जरूर उठी है। अब तक सवालों से घिरी भाजपा शीर्ष के लिए नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना एक्सटेंशन है या एक्सपेरिमेंट और इसके भाजपा की रणनीति कैसी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलवक्त नितिन नवीन का भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने पर पत्रिका प्रबंधन बधाई देता है।●

कटघरे में लालू परिवार
संकट में राजद का अस्तित्व

● **अमित कुमार**

नौकरी के लिए जमीन का मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव पर आरोप तय किए। अदालत ने भ्रष्टाचार की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि लालू परिवार ने अधिकारों का दुरोपयोग किए। पूरा परिवार आपराधिक साजिश में शामिल है। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य सहित सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। बताते चले कि लालू परिवार पर आरोप हैं कि 2004 से 2009 तक लालू यादव के रेल मंत्री रहते उन्होंने नौकरी के नाम पर परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई। उन पर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम अपने नाम कराने का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक, लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों या उनके परिजनों से जमीन ली गई। यह जमीन बाद में लालू परिवार या उनके

करीबी लोगों के नाम पर ट्रांसफर कराई गई। लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए ही बिना कोई विज्ञापन जारी कर रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरी के लिए कई लोगों की भर्ती की थी। लालू के दबाव में ऐसे लोगों को ग्रुप-डी की नौकरियां दी गई, जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि चयनित अभ्यर्थियों ने या तो लालू यादव, उनके परिजन या उनसे जुड़े लोगों के नाम पर जमीन उपहार में दी गई या कम कीमत पर बेची थीं। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने बताया था कि नौकरी पाने वाले सभी अभ्यर्थी बिहार के बेहद गरीब तबके से थे। उनके पास जो दस्तावेज थे, वे फर्जी स्कूलों से जारी हुए थे। बता दें कि साल 2017 में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा आईआरसीटीसी के अफसरों तथा कुछ अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि साल 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब आपराधिक साजिश रच आईआरसीटीसी के होटलों

के टेंडर पटना और ओडिशा के पुरी में मनपसंद पार्टियों को दी गई थी। इसके बदले में रिश्वत के तौर पर जमीन ली गई थी। इस मामले में आगे की जांच के बाद सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और 11 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जांच एजेंसी का दावा है कि यह पूरा खेल एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। हालांकि, लालू परिवार और अन्य आरोपियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि चार्जशीट में नामजद कुल 103 आरोपियों में से पांच की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी के खिलाफ सबूतों के आधार पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ट्रायल की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। बता दें कि उक्त मामले में सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120, 420, 468, 467, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 9 11, 12 और 13 के तहत आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर की थी।

गौरतलब है कि देश के चर्चित आईआरसीटीसी घोटाला केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने इस चर्चित केस में लालू यादव पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। ट्रायल कोर्ट की इस कार्यवाही के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन लालू यादव को हाईकोर्ट से झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। लालू प्रसाद यादव ने कथित आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) घोटाला मामले में उनके और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव तथा 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए जाने संबंधी विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। इससे पहले 13 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। लालू यादव के

विशाल गोगने

अलावा, अदालत ने प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 13(2) ((धारा 13(1)(डी)(ii) एवं (iii) के साथ पढ़ा जाए) के तहत आरोप तय किए थे। धारा 13(2) लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए दंड से संबंधित है और धारा 13(1)(डी)(ii) और (iii) लोक सेवक द्वारा पद का दुरुपयोग कर लाभ प्राप्त करने से संबंधित है। अदालत ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय करने का भी निर्देश दिया था। सनद् रहे कि विशेष जज विशाल गोगने की अदालत ने आदेश सुनाते हुए लालू परिवार को आपराधिक उपक्रम चलाने और रेलवे को अपनी जागीर बनाने जैसी टिप्पणी की। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत में पढ़े गए आदेश में जज गोगने ने कहा कि "चार्जशीट से पता चलता है कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य एक क्रिमिनल एंटरप्राइज (आपराधिक उपक्रम) चला रहे थे। वे

मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?

☞ **18 मई 2022**- CBI ने दर्ज की एफआईआर।

☞ **10 अक्टूबर 2022**- सीबीआई ने लालू, राबड़ी और मीसा समेत 16 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोपपत्र दाखिल किया।

☞ **फरवरी 2023**- राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार समेत अन्य 14 आरोपियों को समन जारी कर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

☞ **जून 2024**- सीबीआई ने अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया।

☞ **मई 2025**- दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू यादव की सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी और आरोपपत्र रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।

☞ **अगस्त 2025**- अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश की गई दलीलें।

☞ **सितंबर 2025**- दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 अक्टूबर के लिए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

☞ **अक्तूबर 2025**- 10 नवंबर तक फैसला सुरक्षित रखा गया।

☞ **नवंबर 2025**- कई बार स्थगित हुआ फैसला।

☞ **19 दिसंबर 2025**- सीबीआई ने कोर्ट में आरोपियों की स्थिति के बारे में एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें कहा गया कि आरोपपत्र में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है।

☞ **9 जनवरी, 2026**- लालू परिवार समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय हुए, 52 आरोपियों को बरी किया गया।

एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने संपत्ति हासिल करने के लिए सरकारी नौकरियों की सौदेबाजी की। लालू के करीबी लोगों ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरियां दिलाने में मदद की। लालू और उनके परिवार के सदस्यों की बरी होने की अपील पूरी तरह अनुचित है। ऐसा लगता है कि लालू यादव ने रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर के तौर पर इस्तेमाल किया था।" वही बताते चले कि दिए गए आदेश में विशेष अदालत ने इस केस में कुल 103 में से 52 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि 5 की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने लालू परिवार के सदस्यों समेत 41 के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह माना कि मामले में आगे ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। अब अगली प्रक्रिया के तहत गवाहों और सबूतों के आधार पर मुकदमे की सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

विदित हो कि लैंड फॉर जॉब केस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है, बल्कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुराने बयानों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई तीखी नोकझोंक की चर्चा भी एक बार फिर शुरू हो गई है। इस मामले के बाद खासतौर पर 2017 में दिया गया तेजस्वी यादव का वो बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था- "जब मेरी मूंछ नहीं निकली थी, तब मेरे बारे में कहा जा रहा था कि मैंने भ्रष्टाचार किया है।" उस वक्त सीबीआई की छापेमारी और जांच पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा था कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि क्या पिछड़े परिवार से होने की वजह से उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। तेजस्वी का कहना था कि जब कथित घटनाएं हुई, उस समय वे नाबालिग थे, ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। ज्ञात हो कि 2025 में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को "बच्चा" बताते हुए कहा था-"तुम लोगों को कुछ नहीं आता, अभी बच्चा हो।" नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने ही लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया था और 2005 में जब वे सत्ता में आए, तब बिहार की क्या स्थिति थी, यह सबको पता है। इस बयान के बाद आरजेडी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में हुई शिक्षकों की नियुक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि सारा काम उनकी सरकार ने किया। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि उस समय सरकार आरजेडी की थी। जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि "एक बार गड़बड़ी

रामकृपाल यादव

तेजस्वी यादव

संजय सिंह

की तो हटाया गया, दूसरी बार भी गड़बड़ी हुई तो हटाना पड़ा।" इस बयानबाजी ने बिहार की राजनीति में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच की तल्खी को और उजागर कर दिया। अब जब कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय कर दिए हैं, तो विपक्ष इस पुराने बयान को लेकर तेजस्वी पर तंज कस रहा है, वहीं आरजेडी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है।

गौरतलब है कि लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय होने के बाद साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की राजनीति में भी इसका असर दिखेगा। एक तरफ बीजेपी और एनडीए इस मुद्दे को लेकर आरजेडी पर हमलावर हैं, वहीं आरजेडी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। अब सबकी निगाहें अदालत में होने वाले ट्रायल पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या सीबीआई अपने आरोपों को ठोस सबूतों के जरिए साबित कर पाएगी या आरजेडी नेताओं का यह दावा सही साबित होगा कि यह मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। फिलहाल, आरोप तय होते ही तेजस्वी यादव के पुराने बयान और नीतीश कुमार के तंज ने बिहार की सियासत में नई बहस जरूर छेड़ दी है। दूसरी तरफ एनडीए नेताओं की ओर से लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में टूट के दावे हो चुके हैं। पिछले दिनों भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने कहा था कि आरजेडी के विधायकों में बेचैनी है और वे लगातार एनडीए के संपर्क में हैं। कई विधायक पाला बदलकर सरकार के समर्थन में आ जाएंगे। वही चुनाव में हार और लैंड फॉर जॉब केस में चार्जशीट की दंश झेल रहे राजद और लालू परिवार पर बीजेपी नेता और नीतीश कुमार सरकार में कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजद के 25 में से 20 विधायक उनके संपर्क में हैं। वे कभी भी एनडीए के पाले में आ सकते हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को विदेश यात्रा से निकलकर जनता के बीच बने रहने की नसीहत दी है। कभी लालू प्रसाद यादव के हनुमान रहे राम कृपाल यादव ने कहा है कि जनता ने राजद को समाप्ति की ओर भेज दिया है। पिछले चुनाव में उनके 78 विधायक थे। इस बार 25 पर समेट कर रख दिया। इनमें से बीस मेरे संपर्क में हैं। वे कभी भी इधर आ सकते हैं। तेजस्वी यादव और उनके नेता कार्यकर्ता अपना दर्द छिपाने के लिए कुछ-कुछ बोलते रहते हैं। मीडिया कर्मियों से पटना में बात करते हुए राम कृपाल यादव ने कहा कि राजद के दिन चले गए। लाख प्रयास कर लें लेकिन सफल नहीं होंगे। लाख प्रयास कर लें पर कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता ने दिल से उतार दिया है। यह भी कहा कि राजद को अपने विधायकों को संतुष्ट रखना चाहिए। तेजस्वी यादव विदेश दौड़े पर हैं पर उनके विधायक छिटक रहे हैं। वे जनता से भी दूरी पर रहते हैं। राजद का सरकार बनाने और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। राम कृपाल यादव इससे पहले भी ऐसा दावा कर चुके हैं। एक बार फिर बात दोहराने से सियासी महकमे में चर्चा का विषय बन गया है। दूसरी तरफ नीतीश सरकार में मंत्री संजय सिंह ने कांग्रेस विधायकों के भी पाला बदलने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक पाला बदलकर एनडीए में आ जाएंगे। इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार सरकार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) कोटे से मंत्री बने संजय सिंह ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक लगातार एनडीए के संपर्क में हैं। बस कुछ दिन और बाकी हैं। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में आ जाएंगे। इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को यह एहसास है कि बिहार की जनता की निष्ठा नीतीश कुमार के प्रति है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर खेला होने की बात कही जा रही है। वहीं, विपक्ष की ओर से मंत्री के इस दावे को खारिज किया गया है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अनैतिक कामों के लिए मशहूर है। उसे सरकार चलाने का मौका मिला है, तो पलायन, बेहतर गवर्नेंस, गरीबी उन्मूलन जैसे विषयों की बात करनी चाहिए। वह बेवजह ऐसा वातावरण बना रही है। हालांकि, पाला बदलने के इन दावों में कितना सच्चाई है, यह आने वाले समय में पता चलेगा।

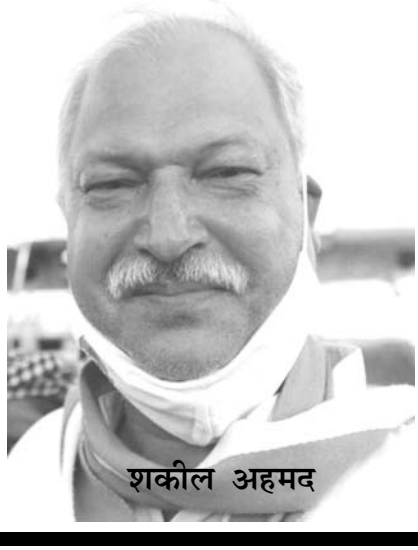
शकील अहमद

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद साल 2026 की शुरुआत में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा

नीरज कुमार

है। वही कोर्ट के फैसले पर सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी और जदयू के प्रवक्ताओं ने लालू परिवार पर पॉलिटिकल-क्रिमिलन सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की है, साथ ही यह भी डिमांड किया है कि देश भर में लालू परिवार की संपत्तियों की जांच की जाए। स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला आते ही लालू परिवार पर हमले की झड़ी लग गई। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव का पूरा परिवार पॉलिटिकल -क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। कोर्ट के निर्णय से यह साबित हो गया। भ्रष्ट आचरण से अकूत सम्पत्ति बनाने का टूल समझकर राजनीति करते हैं। पूरे देश में इस परिवार की संपत्ति है। इस परिवार ने बिहार के सरकारी खजाने को लूटकर अपनी संपत्ति बनाई है। बिहार की गरीब जनता को लूटा है। उन्होने तेजस्वी यादव पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि वे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। कोर्ट के ऑर्डर से देश में लैंड किए हैं नहीं तो अबतक विदेश में छुट्टियां मनाते रहते। नीरज कुमार ने कहा कि भारत का कानून सबके लिए बराबर है। पहले जनता ने 25 सीटों पर समेट दिया। अब कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू परिवार को घेरा। उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह कहना कि क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट लालू परिवार चला रहा था, बहुत शर्मनाक है। लालू यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। राबड़ी देवी के परिजन नाटा चौधरी से भी लालू यादव ने नौकरी के बदले जमीन ले लिया। उन्हें भी विधान परिषद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव के उपनाम तरुण के नाम से संपत्ति ली गई। उनके चाचा मंगरु राय से जमीन लिया गया। यह फेहरिस्त लंबी है। न्यायपालिका ने इसे सही माना है। तेजस्वी यादव भी इस्तीफा देकर मानकर स्थापित करें। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि जल्द सुनवाई करके इस मामले में फैसला सुनाया जाए। दिगर बात है कि अदालत ने लैंड फॉर जॉब केस के 52 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कुल 103 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस अहम फैसले में अदालत ने 52 आरोपियों को बरी कर दिया। अब इनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा। इन पर आईपीसी की धारा 120बी, 420 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं।

गौरतलब है कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव, पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती, हेमा यादव समेत 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। लालू-राबड़ी फैमिली के सदस्यों में तेजस्वी, तेजप्रताप, मीसा को तो सभी जानते हैं, लेकिन हेमा यादव लोगों के लिए थोड़ा कम जाना पहचाना चेहरा है। तो कौन हैं हेमा यादव? जिन्हे लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी बनाया गया है। तो बता दें कि हेमा यादव लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की पांचवी बेटी हैं। वह बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा से इंजीनियरिंग कर चुकी हैं। हालांकि वह शादी के बाद अपनी फैमिली बिजनेस और घर का काम ही संभालती हैं। हेमा परिवार की वह बेटी हैं जो लाइमलाइट से दूर रहती हैं। खासकर राजनीति से अबतक उनका कोई वास्ता नहीं रहा है। लालू यादव ने 2012 में दिल्ली के एक व्यापारी और राजनीतिक परिवार से आने वाले विनीत यादव ने हेमा की शादी कराई थी। ज्ञात हो कि लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी ने सबसे पहले मीडिया में आकर हेमा यादव का नाम लिया था। सुशील मोदी ने कुछ दस्तावेज मीडिया में सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया था कि लालू यादव ने रेलमंत्री रहते हुए ग्रुप डी में सरकारी नौकरी देने के एवज में गरीबों से जो जमीने ली थी, उसमें कुछ प्लॉट बेटी हेमा यादव के नाम पर भी लिखवाई गई थी। इसके बाद सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमें में कहा गया कि यूपीए-1 में रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के बदले अभ्यर्थियों से जमीन लिखवा ली थी।

हेमा यादव

आरोप लगाया गया था कि जमीन पहले दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई, बाद में लालू यादव परिवार के किसी मेंबर के नाम से गिफ्ट करा दी जाती थी। आरोप है कि ऐसे ही एक मामले में 13 फरवरी 2014 को गोपालगंज के हृदयानंद यादव ने लालू की बेटी हेमा यादव को जमीन गिफ्ट की थी। सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि लैंड फॉर जॉब मामले में हेमा यादव ने करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये की दौलत बनाई थी। सुशील मोदी ने ये भी आरोप लगाया था कि हेमा यादव को केवल लालू यादव के घर में काम करने वाले ललन चौधरी ने ही 62 लाख रुपये की जमीन 13 फरवरी 2014 को दान में नहीं दी थी, बल्कि उसी दिन पटना के राजेन्द्र नगर स्थित रेलवे के कोचिंग कॉम्पलेक्स में कार्यरत हृदयानंद चौधरी ने भी हेमा यादव को अपनी संपत्ति दान कर दी थी। सुशील मोदी के आरोप में यह भी कहा गया था कि दान पत्र पर हेमा यादव का पता पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी मां राबड़ी देवी का पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास का पता दर्ज है। दरअसल लालू-राबड़ी की बेटी हेमा यादव के नाम के पीछे ऐक्ट्रेस हेमा मालिनी का कनेक्शन है। बात अक्टूबर 2016 की है, तब बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। इसी दौरान बिहार सरकार के आर्ट और कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हेमा मालिनी के डांस ग्रुप परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। लालू यादव अपने दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव के साथ हेमा मालिनी का डांस देखने पहुंचे थे। कार्यक्रम के अंत में मंच पर पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वह हेमा मालिनी की

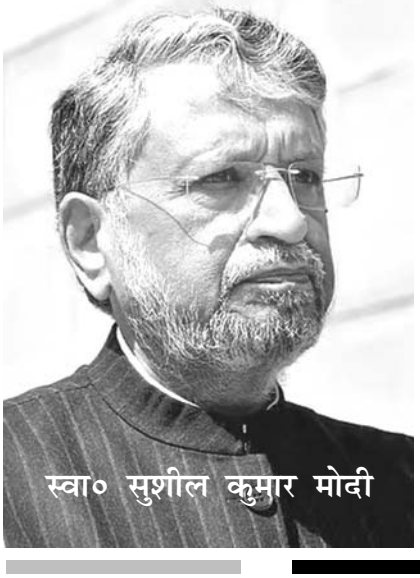
स्वा० सुशील कुमार मोदी

कला के प्रेमी रहे हैं। उन्हें हेमा मालिनी की ऐक्टिंग और डांस बहुत पसंद है। इसी वजह से उन्होंने अपनी एक बेटी का नाम हेमा रखा है। हेमा यादव भले ही राजनीति से दूर हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए समसायिक मुद्दों पर अपनी राय रखती रही हैं। हेमा खासकर बीजेपी पर खूब हमलावर रही हैं। हाल ही में रेप केस के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के जेल से बाहर आने पर हेमा यादव ने सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ कई पोस्ट किए थे।

बहरहाल, देश के रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव खुद तो चारा घोटाला में जेल गए ही, अब उनके आधे परिवार पर जेल जाने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में लालू की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, दोनों बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, दो बेटियों सांसद मीसा भारती और हेमा यादव पर मुकदमा का ट्रायल चलाने के लिए आरोप गठन कर दिया है। आरोप साबित हुए तो परिवार के लोग ना सिर्फ जेल जाएंगे, बल्कि एक समय तक चुनाव लड़ने से भी अयोग्य हो जाएंगे। लालू की राजद की राजनीति इस समय तेजस्वी यादव के हाथों में है। तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर हैं और वो अपनी पार्टी जेजेडी बना चुके हैं। मीसा भारती लोकसभा सांसद हैं। राबड़ी विधान परिषद सदस्य हैं। हेमा यादव राजनीति में नहीं हैं। भारतीय कानून के मुताबिक यदि किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो गई है तो उससे संसदीय या विधायकी पद छीन लिया जाता है और उसे सजा काटने के आगे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है। लालू परिवार के चार बच्चे राजनीति में हैं, जिसमें रोहिणी आचार्या के अलावा तीन नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में ट्रायल स्टेज तक पहुंच गए हैं। अब अदालत में सबूत, गवाही और बहस के बाद इस केस में आरोपियों को या तो सजा होगी या रिहाई। मामले की स्पीडी ट्रायल की गुंजाइश भी है, जिससे केस के फैसले में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। आरोप में जो धाराएं हैं, उनमें 2 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है। ऐसे में अगर कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ लगे आरोपों को ट्रायल में सही मानकर उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुना दी तो लालू की पार्टी राजद के भविष्य की राजनीति पर भी गंभीर सवाल पैदा हो जाएगा। सजा मिलने पर लालू-राबड़ी परिवार की दूसरी पीढ़ी से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती सजा काटने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। राजद की राजनीति चाहे-अनचाहे लालू परिवार में रोहिणी आचार्या, तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव या किसी और बेटी के हाथ जा सकती है। पार्टी का कोई और नेता भी उभारा जा सकता है। राजद का यह संकट भविष्य की बात है, लेकिन आरोप गठन ने लालू खानदान और उनकी पारिवारिक राजनीति को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है।●

राजधानी दिल्ली में 'श्री गुरु गोबिंद सिंह केवल सच सम्मान-2025' का भव्य आयोजन

● अमित कुमार

हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता और विशिष्ट पहचान बनाने वाली प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका 'केवल सच' ने अपने प्रकाशन के 20 गौरवशाली वर्ष पूरे कर एक ऐतिहासिक पड़ाव हासिल किया है। इस अभूतपूर्व अवसर को यादगार बनाने के लिए, राजधानी दिल्ली स्थित कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के मावलंकर सभागार में सिखों के दसवें गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मोत्सव की संध्या बेला पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक हजार से अधिक दर्शकों और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए सम्मानित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया।

इस ऐतिहासिक समारोह का सबसे महत्वपूर्ण क्षण श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मोत्सव की संध्या

बेला पर केंद्रित 'धर्म-न्याय की रक्षा में साहिबजादों की कुर्बानी, गुरू गोबिंद सिंह का बलिदान...' विशेषांक का लोकार्पण रहा। यह विशेष अंक श्री गुरू गोबिंद सिंह जी के असाधारण जीवन, त्याग, साहस, समानता और बलिदान को दिखाता है।

समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ हुआ, जो भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रिका के दूरदर्शी संपादक और संस्थापक श्री ब्रजेश मिश्र ने की, जिनके अथक प्रयासों और प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि 'केवल सच' ने यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। मंच पर अनेक गणमान्य हस्तियाँ उपस्थित थीं, जिनमें आनंद केडिया (मुख्य प्रधान आयुक्त), पी. वी. भजंत्री (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय), इंद्रेश कौशिक जी महाराज (प्रसिद्ध कथावाचक), संजय मयूख (माननीय पार्षद) एवं गुरप्रीत सिंह रम्मी (प्रसिद्ध 'ऑक्सीजन

मैन'), सरदार वलजिंदर सिंह दकोहा (अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजहवी सिख फेडरेशन) आदि प्रमुख थे। इन सभी विभूतियों की उपस्थिति ने समारोह में चार चाँद लगा दिए। सभी अतिथियों ने गुरू गोबिंद सिंह के न्याय, धर्म की रक्षा के लिए अपनी मां और बच्चों के बलिदान पर प्रकाश डालते हुए उक्त कार्यक्रम को लेकर पत्रिका प्रबंधन और संपादक सह संस्थापक ब्रजेश मिश्र जी को बधाई दी।

बताते चले कि श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट एवं केवल सच राष्ट्रीय पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "गुरु गोबिंद सिंह केवल सच सम्मान-2025" के अंतर्गत संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्य करने वाले प्रबुद्ध व्यक्तित्वों को सम्मानित कर उनके योगदान को सार्वजनिक मंच पर रेखांकित करना रहा। बता दें कि "गुरु गोबिंद सिंह केवल सच सम्मान-2025" से जो सम्मानित हुए उन सदस्यों के नाम और उनके कार्य क्षेत्र निम्नवत् है:-

(1) प्रकाश मिश्र-समाज सेवा, प्रशासन
(2) शंकरानन्द ठाकुर-सामाजिक कार्याकर्ता
(3) दुर्गेश तिवारी-उद्यम युवा
(4) ब्रजेश सहाय-पत्रकार, आटीआई
(5) डॉ० राज शर्मा-सामाजिक कार्य
(6) गौतम चौधरी-लेखक
(7) मनोज भारती-व्यवसाय
(8) सोनू कुमार-पत्रकार
(9) जगदीप सिंह-पत्रकार
(10) हरजीत सिंह-सामाजिक
(11) संदीप नायर-सामाजिक
(12) त्रिलोचन सिंह-सामाजिक

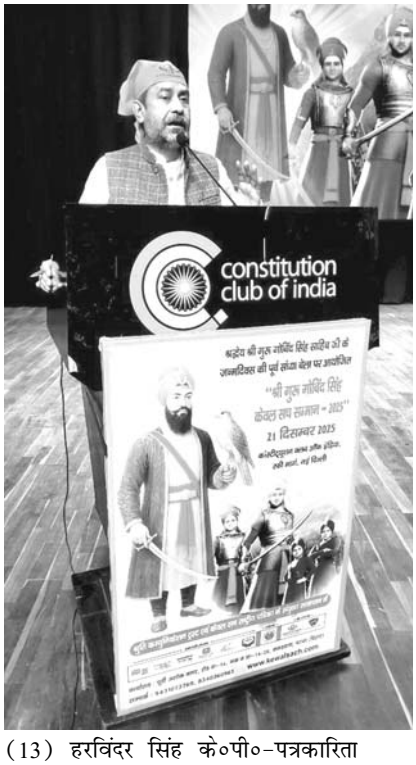

(13) हरविंदर सिंह के०पी०-पत्रकारिता
(14) सुरिन्दर कौर-सामाजिक
(15) मनोज कुमार यादव-सामाजिक
(16) मो० कमर साबरी-पत्रकारिता
(17) सत्यपाल सिंह-सामाजिक
(18) साबेद भूयन-उद्योग
(19) सन्नी छाबड़ा-सामाजिक
(20) कवि राजपाल सिंह-लेखनी
(21) जगदीप सिंह कालोजी-सामाजिक

(22) हरमीत सिंह पप्पा जी-सामाजिक
(23) विजय पाठक-पत्रकार, संपादक
(24) सुश्री मिनाक्षी श्रृयान-पत्रकार
(25) अवतार सिंह भूरजी-समाजिक
(26) बलजीत सिंह जी-सामाजिक
(27) सक्तर सिंह-सामाजिक
(28) पूनम बिसनोई-सामाजिक
(29) मंजीत सिंह-प्रधान, श्याम पार्क गुरूद्वारा
(30) चरणजीत सिंह पासी-पत्रकार
(31) कुलदीप सिंह-समाज सेवा
(32) गुरजीत सिंह-समाज सेवा
(33) कुलवंत सिंह-सचिव, नंदग्राम गुरूद्वारा
(34) अवतार सिंह-प्रधान, नंदग्राम गुरूद्वारा
(35) प्रितम सिंह-चेयरमैन, नंदग्राम गुरूद्वारा
(36) नीतु बिसनोई-सरकारी अधिवक्ता
(37) हरवंश सिंह-राय सिख कम्युनिटी
(38) जगजीत सिंह मिल्खा-पूर्व विधायक (बीजेपी), पंजाब
(39) वशिष्ठ पाण्डेय-प्रदेश अध्यक्ष, आईटी सेल (लोजपा), दिल्ली
(40) सुधांशु झा-भाजपा नेता पूर्वांचल मोर्चा, दिल्ली
(41) संजय कुमार सिन्हा- स्टेट हेड (केवल सच राष्ट्रीय पत्रिका), नई दिल्ली
(42) संजय पाण्डेय-सी.ए., नई दिल्ली
(43) केशव कुमार-व्यवसायी, चंडीगढ़
(44) रविन्द्र सिंह राणा-सामाजिक
(45) जगदीप सिंह गुजराल-सामाजिक

कार्यक्रम के समापन पर 'केवल सच' के संपादक श्री ब्रजेश मिश्र ने सभी दर्शकों, अतिथियों, पत्रकार साथियों, संरक्षकों और पाठकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी 20 वर्षों की यात्रा को संघर्षों से भरा बताया, साथ ही यह भी कहा कि उनकी टीम,

विज्ञापनदाताओं और पाठकों द्वारा दिखाए गए अटूट विश्वास के कारण ही वे इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। श्री मिश्र ने अपनी पत्रिका की मूल भावना को दोहराते हुए कहा, हमारी पत्रिका हमेशा उन विभूतियों को सामने लाने का कार्य करती रही है, जिन्होंने समाज में बदलाव की अलख जगाई है। यह समारोह न केवल 'केवल सच' के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा, विशेषकर गुरू गोबिंद सिंह जी के त्याग, बलिदान और धर्म रक्षा के प्रति निष्ठा के लिए दिये गये अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने का भी एक सार्थक और प्रेरणादायक प्रयास रहा। 'धर्म-न्याय की रक्षा में साहिबजादों की कुर्बानी, गुरू गोबिंद सिंह का बलिदान...' जैसे विशेषांक को पढ़ने के बाद अतीत के संघर्षों से परिचित कराकर पाठकों के बीच प्रेरणा जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने सभी उपस्थित लोगों को एकजुटता और राष्ट्रीय गौरव की भावना से भर दिया। वक्ताओं ने केवल सच के संघर्ष के 20 वर्ष पुरे होने पर पूरी टीम की निष्ठा और सहयोग की भावना के लिये अपनी शुभकामनायें देतें हुए कहा की जब सरकार मध्यम एवं छोटी पत्रिकाओं को आर्थिक सहयोग न कर उसकी स्वतन्त्राता पर भी अंकुश लगाने का प्रयास कर रही हैं, वैसे समय में भी केवल सच पत्रिका निरंतर अपनी कर्तव्यों एवं पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए सरकार को आईना दिखाया साथ ही अच्छे कार्यों की प्रसंशा से भरी खबरों का प्रकाशन भी करते रहा। आज 'केवल सच' देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपने प्रकाशन से सरकार एवं आम लोगों तक अपनी गहरी पैठ बना चूका है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों पत्रकार, बुद्धिजीवी, चिकित्सक, अधिवक्ता, समाजसेवी सहित हजारों लोग उपस्थित थे, जो 'केवल सच' की जन-जन तक पहुँच और उसके प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। ●

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)**

उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों मतदाता सूची के एक तकनीकी से दिखने वाले, लेकिन असर में बेहद सियासी मुद्दे के इर्द-गिर्द घूम रही है. स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर को लेकर ऐसा घमासान मचा है कि यह प्रक्रिया 2027 के विधानसभा चुनाव की बुनियाद बनती नजर आ रही है. चुनाव आयोग इसे नियमित और जरूरी कवायद बता रहा है, जबकि राजनीतिक दल इसे अपने-अपने चश्मे से देख रहे हैं. एक तरफ बीजेपी फर्जी, डुप्लीकेट और घुसपैठियों के नाम हटाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष को आशंका है कि इस प्रक्रिया की आड़ में गरीब, अल्पसंख्यक और प्रवासी तबके के वोट काटे जाएंगे. एसआईआर की शुरुआत 1 नवंबर 2025 से हुई. जनवरी 2025 की मतदाता सूची के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे. आयोग का उद्देश्य साफ है मृत मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों, दोहरी प्रविष्टियों और फर्जी नामों को हटाना, साथ ही नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना. इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए घर-घर सत्यापन कराया गया. यह प्रक्रिया पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार विवाद इसलिए गहरा गया क्योंकि सत्ताधारी दल के शीर्ष नेताओं के बयान सियासी आग में घी डालने लगे.

14 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि एसआईआर के बाद प्रदेश की मतदाता सूची से करीब चार करोड़ नाम हट सकते हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि इनमें से 85 से 90 फीसदी नाम बीजेपी समर्थकों के हैं. यह बयान आते ही सियासी हलकों में खलबली मच गई. सवाल उठने लगे कि अगर वास्तव में चार करोड़ नाम हटते हैं तो यह प्रदेश की राजनीति का चेहरा बदल सकता है. योगी के मुताबिक, अब तक करीब 12 करोड़ नाम ही रिकॉर्ड हो पाए हैं, जबकि आबादी के अनुपात में यह संख्या ज्यादा होनी चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बूथ स्तर पर सक्रिय होकर छूटे हुए नामों को जोड़वाएं. योगी के बयान के कुछ ही दिन बाद, 17 दिसंबर को पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एक अलग ही दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की तीन विधानसभा सीटों में ही करीब तीन लाख नाम कट सकते हैं और ये ज्यादातर समाजवादी पार्टी के वोटर हैं. यह बयान योगी के दावे से उलट दिशा में जाता दिखा. एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों के नाम ज्यादा कट रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता दावा कर रहे हैं कि नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा. यहीं से एसआईआर पर सवाल और

गहरे हो गए.

विपक्ष ने इन बयानों को हाथों हाथ लपक लिया. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अगर चार करोड़ नामों में 85 फीसदी बीजेपी के हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी के साढ़े तीन करोड़ वोटर फर्जी थे. उन्होंने चुनाव आयोग से पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर वोट काटने की साजिश रची जा रही है, खासकर उन इलाकों में जहां गरीब, मजदूर और अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है.असल में, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जनवरी 2026 में आएगी और फाइनल सूची फरवरी में प्रकाशित होगी. यानी फिलहाल जो भी दावे किए जा रहे हैं, वे प्राथमिक फीडबैक, कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट और अनुमान पर आधारित हैं. यही वजह है कि आंकड़ों से ज्यादा बयानबाजी सुर्खियों में है. योगी आदित्यनाथ के चार करोड़ वाले दावे के पीछे जो गणित बताया जा रहा है, वह भी चर्चा में है. यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ मानी जाती है. अगर इसमें 65 फीसदी वयस्क मतदाता मानें, तो आंकड़ा करीब 16 करोड़ के आसपास बैठता है. इसमें हर साल 18 साल पूरे करने वाले नए वोटरों को जोड़ना भी शामिल है. ऐसे में 12 करोड़ नाम रिकॉर्ड होने की बात सुनकर चार करोड़ का अंतर निकालना आसान है. लेकिन यह अंतर वास्तव में नाम कटने का है या अब तक सत्यापन में न आ पाने का, यह साफ नहीं है.

बीजेपी के भीतर भी यह माना जा रहा है कि शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते हैं, लेकिन गांव का वोट बनाए रखते हैं. सत्यापन के समय ऐसे कई नाम छूट जाते हैं. योगी का जोर इस बात पर था कि पार्टी कार्यकर्ता समय रहते ऐसे मतदाताओं का फॉर्म भरवाएं. उनके भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठियों और उम्र में गड़बड़ी वाले उदाहरण भी आए, जिसने पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान की राजनीति से जोड़ दिया.दूसरी ओर, सुब्रत पाठक का बयान कन्नौज जैसे समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ से जुड़ा है. 2019 में यहां से सांसद रहे पाठक 2024 में अखिलेश यादव से चुनाव हार चुके हैं. ऐसे में उनके बयान को स्थानीय सियासत और 2027 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. उनका दावा है कि फर्जी और डुप्लीकेट नामों का सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है और एसआईआर के बाद उसकी असलियत सामने आ जाएगी. हालांकि, इस दावे के समर्थन में भी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है.

चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और किसी भी नाम को हटाने से पहले नोटिस और अपील का मौका दिया जाता है. आयोग का कहना है कि अंतिम सूची आने से पहले किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. इसके बावजूद राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही. अगर दूसरे राज्यों के अनुभव देखें तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है. बिहार और पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर में बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं के नाम जुड़े हैं, जबकि मृत, डुप्लीकेट और लंबे समय से बाहर रह रहे लोगों के नाम कटे हैं. वहां किसी एक पार्टी को सीधा फायदा या नुकसान होने की बात साफ तौर पर सामने नहीं आई. यूपी में भी यही पैटर्न दोहराया जा सकता है, लेकिन यहां का पैमाना और सियासी दांव कहीं बड़े हैं. सवाल आखिर में यही है कि मतदाताओं की संख्या घटने या बढ़ने से फायदा किसे होगा. इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किन इलाकों में, किस सामाजिक वर्ग के और किस उम्र के मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होते हैं या जुड़ते हैं. फिलहाल इतना तय है कि एसआईआर ने 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. जब तक जनवरी-फरवरी 2026 में आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक योगी हों या अखिलेश, हर बयान सियासत का हिस्सा बना रहेगा और वोटर लिस्ट राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनी रहेगी. ●

योगी के ब्राह्मण और ठाकुर विधायक अलग-अलग लामबंद

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार छोटी घटनाएं बड़े सियासी बदलावों का संकेत देती हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में हुआ एक सहभोज भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। कुशीनगर से भाजपा विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर 22 दिसंबर की शाम आयोजित इस कार्यक्रम को बाहर से निजी और पारिवारिक बताया गया, लेकिन इसमें शामिल चेहरों, समय और माहौल ने इसे राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। सत्र के बीच राजधानी में बड़ी संख्या में ब्राह्मण विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का एक साथ जुटना सामान्य नहीं माना जा रहा। जानकारी के मुताबिक, इस सहभोज में करीब 35 से 40 विधायक और एमएलसी शामिल हुए। इनमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, लेकिन कुछ अन्य दलों के ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी भी सामने आई। मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्र, देवरिया से डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, बांदा से प्रकाश द्विवेदी, तरबगंज से प्रेम नारायण पांडेय, बदलापुर से रमेश मिश्र, महनौन से विनय द्विवेदी और एमएलसी साकेत मिश्र जैसे नामों ने बैठक को राजनीतिक रूप से अहम बना दिया। भोजन में लिट्टी-चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया, जिसे आयोजकों ने सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा से जोड़ा।

यूपी विधानसभा में मौजूदा समय में ब्राह्मण विधायकों की संख्या 52 बताई जाती है, जिनमें से 46 भाजपा के हैं। यह आंकड़ा खुद में यह बताने के लिए काफी है कि सत्ता पक्ष में यह समाज कितना प्रभावशाली है। बावजूद इसके, हाल के महीनों में पार्टी के भीतर यह चर्चा जोर पकड़ती रही है कि संगठन और सरकार में संतुलन बदल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कुर्मी समाज से आने वाले नेता को मिलने के बाद यह भावना और मजबूत हुई कि ब्राह्मण नेतृत्व को अपेक्षाकृत कम अहमियत मिल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज का इतिहास लंबा और प्रभावशाली रहा है। आजादी के बाद दशकों तक सत्ता की धुरी ब्राह्मण नेतृत्व के इर्द-गिर्द घूमती रही। 1990 के दशक में मंडल राजनीति के उभार के बाद समीकरण बदले, पिछड़ी और दलित जातियों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा, लेकिन ब्राह्मण समाज पूरी तरह हाशिये पर नहीं गया। उसने समय-समय पर नए राजनीतिक समीकरणों के साथ खुद को जोड़े रखा। यही कारण है कि आज भी यह समाज भले आबादी में 8 से 10 फीसदी माना जाता हो, लेकिन राजनीतिक असर इससे कहीं ज्यादा रखता है।

चुनावी आंकड़े इस प्रभाव को साफ दिखाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं का करीब 83 फीसदी समर्थन भाजपा को मिला था। 2022 में यह समर्थन बढ़कर लगभग 89 फीसदी तक पहुंच गया। यानी लगातार दो चुनावों में भाजपा को इस वर्ग से मजबूत समर्थन मिला। प्रदेश की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं, जहां ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में ब्राह्मण आबादी 15 फीसदी से अधिक बताई

जाती है। ऐसे में लखनऊ की इस बैठक को केवल सामाजिक सहभोज कहना कई लोगों को अधूरा सच लगता है। राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह जुटान सिर्फ आपसी मेल-मिलाप थी या इसके पीछे भविष्य की रणनीति भी छिपी है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में खुलकर राजनीति पर तो चर्चा नहीं की गई, लेकिन ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों पर चिंता जरूर जताई गई। हाल के दिनों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सामने आई घटनाओं का जिक्र हुआ, जहां ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय या उपेक्षा की शिकायतें सामने आई थीं। ऐसे मामलों में संगठित होकर प्रतिक्रिया देने और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने की बात कही गई।

बताया जा रहा है कि बैठक में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करने पर भी बातचीत हुई। इसमें वकील, डॉक्टर, रिटायर्ड अधिकारी और समाज के प्रभावशाली लोगों को जोड़ने की योजना पर विचार किया गया। मकसद यह बताया गया कि जरूरत पड़ने पर समाज अपने स्तर पर मदद कर सके और किसी पर निर्भर न रहे। इसके साथ ही राजनीतिक हिस्सेदारी

के सवाल पर भी चर्चा हुई कि आबादी और योगदान के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरकार की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सतर्क बयान आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों का मिलना-जुलना स्वाभाविक है और इसे जातीय नजरिए से देखना गलत है। उनका कहना था कि विधायक आपस में मिलते हैं, चर्चा करते हैं और इसे किसी समुदाय विशेष की बैठक कहना सही नहीं है। सत्ता पक्ष के कई अन्य नेताओं ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी।

विपक्ष ने इस बैठक को भाजपा का आंतरिक मामला बताया, लेकिन साथ ही तंज कसने से भी नहीं चूका। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर पार्टी के भीतर इस तरह की बैठकें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि असंतोष कहीं न कहीं मौजूद है। कुछ नेताओं ने इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले की बेचैनी के तौर पर देखा राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक अपने आप में कोई बड़ा आंदोलन नहीं है, लेकिन यह संकेत जरूर देती है कि जातीय संतुलन का सवाल फिर से केंद्र में आ रहा है। पिछले कुछ समय में ठाकुर समाज और फिर कुर्मी समाज से जुड़े कार्यक्रमों की चर्चा सामने आई थी। उसी क्रम में अब ब्राह्मण विधायकों की यह जुटान देखी जा रही है। यह दिखाता है कि सत्ता के भीतर अलग-अलग सामाजिक समूह अपनी भूमिका और हिस्सेदारी को लेकर सजग हो रहे हैं।

2027 का विधानसभा चुनाव अभी समय दूर लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में तैयारियां हमेशा पहले शुरू हो जाती हैं। लखनऊ का यह सहभोज उसी शुरुआती तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा के लिए यह चुनौती है कि वह अपने सबसे मजबूत समर्थक वर्गों में संतुलन बनाए रखे, जबकि विपक्ष के लिए यह मौका है कि वह किसी भी असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करे। फिलहाल, लखनऊ की उस शाम का सहभोज खत्म हो चुका है, लेकिन उससे उठी राजनीतिक चर्चा अभी थमी नहीं है। आने वाले महीनों में अगर ऐसी बैठकों का सिलसिला बढ़ता है, तो साफ हो जाएगा कि यह केवल सामाजिक मेल-मिलाप नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बिसात बिछाने की कोशिश है।●

पंचानंद पाठक

विनय द्विवेदी

प्रेम नारायण पांडेय

रत्नाकर मिश्रा

शलभ मणि त्रिपाठी

रमेश चंद्र मिश्र

प्रकाश द्विवेदी

साकेत मिश्रा

योगी आदित्यनाथ

हजारों करोड़ के कोडीन रैकेट पर सियासी संग्राम

● **संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)**

उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर तेज बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के दौर में प्रवेश कर चुकी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने-सामने आ गए हैं। मामला सिर्फ नशीली दवाओं की तस्करी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें राजनीतिक संरक्षण, माफिया नेटवर्क और हजारों करोड़ के अवैध कारोबार के आरोप जुड़ने के बाद यह एक बड़े सियासी संघर्ष का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सक्रिय रहे अधिकांश माफियाओं के तार किसी न किसी रूप में सपा से जुड़े रहे हैं और कोडीन कफ सिरप तस्करी के मामले में पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के संबंध भी समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष उसी के बाद सामने आएगा, लेकिन प्रारंभिक तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि जब अभियुक्तों के साथ राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें सामने आती हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।

योगी आदित्यनाथ ने शायराना अंदाज में सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि 'धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे'। उनके इस बयान को सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर कटाक्ष के रूप में देखा गया। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे उसका संबंध किसी भी दल या प्रभावशाली व्यक्ति से क्यों न हो। मुख्यमंत्री

Shubham Jaiswal
(Varanasi)

Bhola Prasad Jaiswal

Amit Singh alias Tata
(Jaunpur)

Alok Pratap Singh
(Lucknow)

Sourabh
Tyagi
Meerut-Ghaziabad

Vibhore Rana
Saharanpur

Vishal Singh
Saharanpur

के बयान के कुछ ही समय बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा। बिना मुख्यमंत्री का नाम लिए उन्होंने शायरी के माध्यम से पलटवार किया और आरोप लगाया कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ। अखिलेश यादव के इस बयान को सरकार के आरोपों का सधा हुआ जवाब माना गया। सपा नेताओं का कहना है कि सरकार अपनी नाकामियों और प्रशासनिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष को निशाना बना रही है।

कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप का यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे तौर पर एनडीपीएस अधिनियम से जुड़ा हुआ है। कोडीन एक नियंत्रित औषधि है, जिसका उपयोग सीमित मात्रा में और निर्धारित चिकित्सकीय जरूरतों के लिए किया जाता है। सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में इसका बड़े पैमाने पर नशे के रूप में दुरुपयोग हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और सोनभद्र जैसे जिलों में एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था, जो फर्जी लाइसेंस, शेल कंपनियों और जाली दस्तावेजों के जरिए कफ सिरप की अवैध सप्लाई कर रहा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 37 लाख से अधिक बोतलों की अवैध बिक्री का पता चला है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 57 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जबकि पूरे सिंडिकेट का कारोबार लगभग 2,000 करोड़ रुपये तक आंका जा रहा है। यह सिरप उत्तर प्रदेश से बिहार, पश्चिम बंगाल और

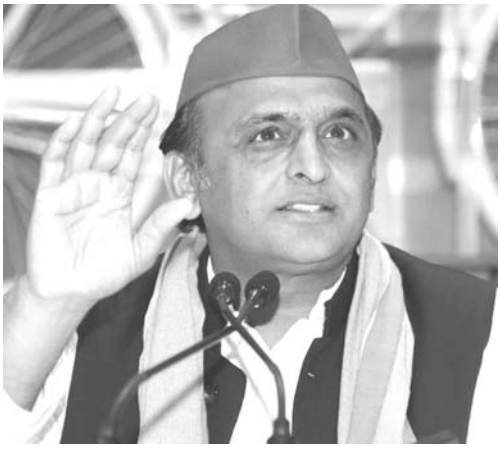

सीमा पार तक भेजा जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि शराबबंदी वाले राज्यों में इसकी मांग अधिक थी, जहां इसे नशे के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।

इस रैकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल बताया जा रहा है, जो कथित तौर पर वाराणसी का एक साधारण मेडिकल सप्लायर था, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसने अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क खड़ा कर लिया। जांच एजेंसियों के अनुसार कोरोना काल के दौरान उसने इस अवैध कारोबार को तेजी से फैलाया। शुभम पर आरोप है कि उसने फर्जी फर्मों के जरिए हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्रियों से कफ सिरप मंगवाया और फिर उत्तर प्रदेश में गुप्त गोदामों के माध्यम से इसकी तस्करी कराई। फिलहाल वह फरार है और उसके दुबई में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने इस पूरे मामले की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय विशेष जांच टीम का गठन किया है, जिसमें यूपी पुलिस, एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी है। अब तक 12 से अधिक दवा कारोबारियों पर केस दर्ज किए जा चुके हैं और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

इस पूरे विवाद के बीच विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्र 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा और इसमें जनहित, विकास और विधायी कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि पहले दिन एक सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण शोक प्रस्ताव के चलते कार्यवाही सीमित रहेगी। इसके बावजूद माना जा रहा है कि कोडीन कफ सिरप तस्करी का मुद्दा सदन के भीतर और बाहर तीखी बहस का केंद्र बनेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनावों की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। एक ओर योगी सरकार इसे नशामुक्त प्रदेश की मुहिम और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तौर पर पेश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश बता रही है। फिलहाल जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है और पूरे प्रदेश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के निष्कर्ष किस ओर इशारा करते हैं।●

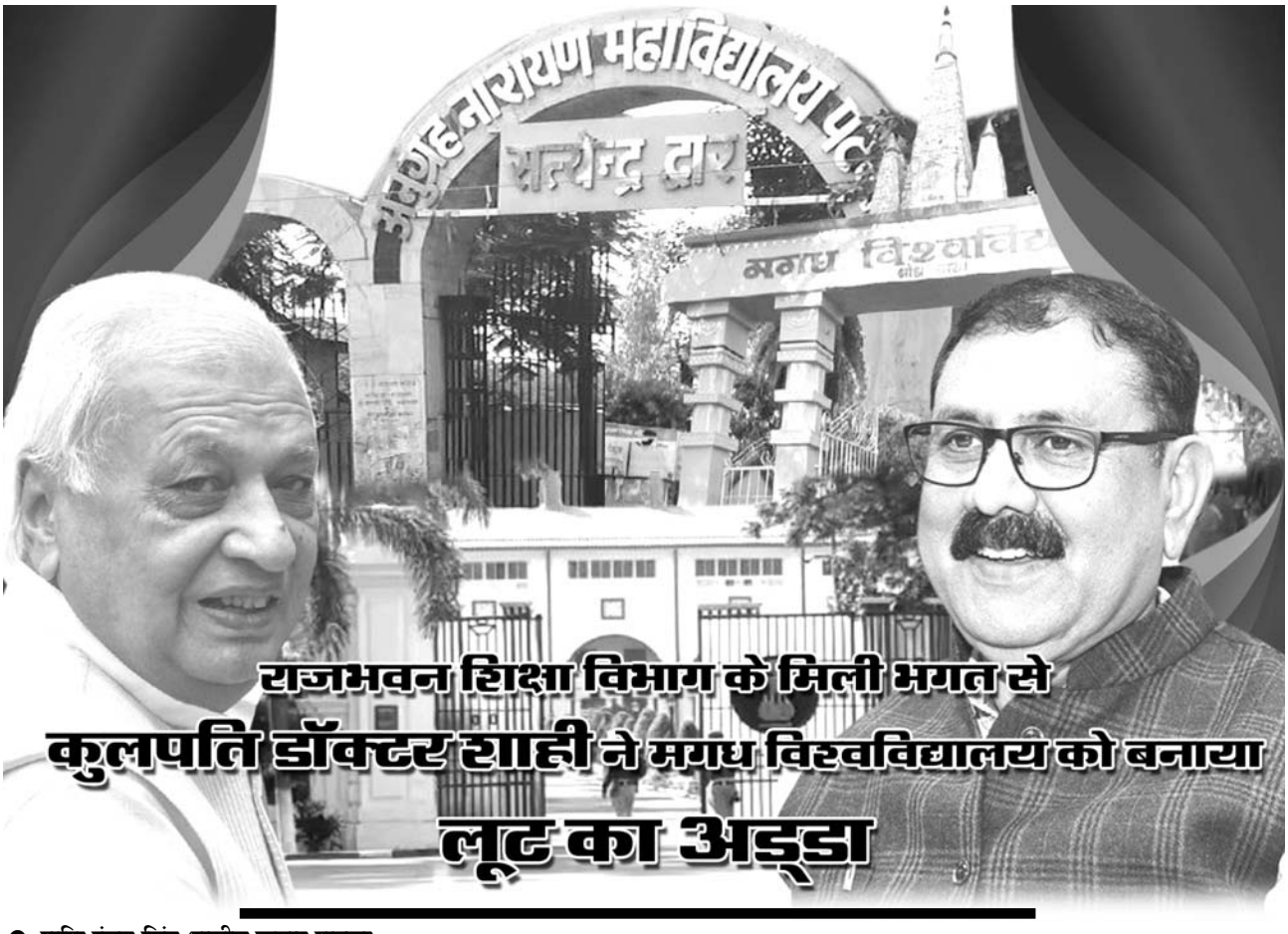

राजभवन शिक्षा विभाग के मिली भगत से कुलपति डॉक्टर शाही ने मगध विश्वविद्यालय को बनाया लूट का अड्डा

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

जब राजनीति में पैसा, लोग और पावर एक साथ काम करने लगता है तो राजनीति में राज और नीति अलग हो जाती है और यह लूट नीति में तब्दील हो जाती है। मगध विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति शशि प्रताप शाही, जो राज भवन और बिहार शिक्षा विभाग के कृपा पात्र हैं, उन्होंने मगध विश्वविद्यालय, गया को लूट का अड्डा बनाकर रख दिया है। आज मगध विश्वविद्यालय, गया इस लूट नीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

समाजसेवी मनीष कुमार और कई गुप्त रूप से शिक्षाविद ने इसकी भ्रष्टाचार की परत दर परत खोलने की भी कोशिश की, लेकिन पैसा और पावर की मजबूत पकड़ के कारण कोई भी डॉक्टर शशि प्रताप शाही का बाल भी बांका नहीं कर सके। हमने भी राजभवन को पत्र लिखकर कुलाधिपति महोदय से इस पर अपना पक्ष जानना चाहा, तो मेरे पत्र को शिकायती पत्र समझकर लोक शिकायत विभाग में अग्रसारित कर दिया गया। कुलाधिपति कार्यालय को इतनी समझ भी नहीं है की प्रेस का पक्ष जानने का पत्र और शिकायती पत्र में अंतर होता है।

केवल सच
ISO 9001 : 2015
www.kewalsach.com www.kewalsachtimes.com www.kewalsachlive.in
महामहिम कुलाधिपति महोदय
राजभवन पटना, बिहार।
विषय- एन कॉलेज पटना के पूर्व प्राचार्य एवं वर्तमान कुलपति मगध विश्वविद्यालय गया श्री शशि प्रताप शाही द्वारा एन कॉलेज पटना के पीएनबी अकाउंट से लगभग 25 लाख रुपए की अवैध केश निकासी के संबंध में।

नोट - इसे अत्यावश्यक समझे क्योंकि यह मामला आर्थिक अपराध से जुड़ा है साथ ही गरीब छात्रों के निधि से भी जुड़ा हुआ है और इस अपराध के श्रेणी में आने वाले सभी लोगों को आर्थिक अपराध के तिए जेल भी जाना पड़ सकता है।

डॉक्टर शशि प्रताप शाही का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वह पटना उच्च न्यायालय के पारित आदेश को भी नहीं मानते हैं। यह मामला पटना उच्च न्यायालय में Civil Writ Jurisdiction Case No.- 11220 of 2009 के रूप में दायर किया गया था। याचिकाकर्ता डॉ. पंकज कुमार ने मगध विश्वविद्यालय से संबंधित एक प्रशासनिक निर्णय को चुनौती दी थी। याचिका का मूल विषय यह था कि डॉ. डी. एन. मिश्रा को मगध विश्वविद्यालय में डीन (Dean, Law Faculty) के पद पर नियुक्ति जारी रखा गया, जबकि यह नियुक्ति विश्वविद्यालय के कानून (Statute) का घोर उल्लंघन था। माननीय न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने यह स्पष्ट किया कि :- विश्वविद्यालय के कुलपति (Vice Chancellor) को बाद में यह एहसास हुआ कि डॉ. डी. एन. मिश्रा को डीन के पद पर बनाए रखना नियमों के विरुद्ध

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.11220 of 2009

Pankaj Kumar @ Dr. Pankaj Kumar son of Sri Navin Chandra Prasad, resident of Mohalla Tilha Kali Bari, Police Station Civil Lines, District Gaya .... Petitioner/s

Versus

1. The State Of Bihar through the Secretary, Higher Education, Govt. of Bihar, Patna
2. Magadh University, Bodh Gaya through Registrar
3. The Vice Chancellor, Magadh University, Bodh Gaya
4. The Registrar, Magadh University, Bodh Gaya
5. The Principal, Nawada Vidhi Mahavidyalaya, Nawada
6. Dr D. N. Mishra, Principal Nawada Vidhi Mahavidyalaya, Nawada, presently the Dean, Law Faculty, Magadh University, Bodh Gaya .... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Pramod Kumar, Advocate
For the State : Mr. GA 2
For the University : Mr Anil Sinha, Advocate
For Respondent 5 & 6 : Mr Y. V. Giri, Sr Advocate
Mr Ashish Giri, Advocate

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE AJAY KUMAR TRIPATHI
ORAL ORDER

7 06-02-2013 Now, since the Vice Chancellor has realized the folly of continuance of the private respondent as a Dean in gross violation of the statute and has brought curtains upon the continuance of the private respondent, Dr D. N. Mishra, as a Dean, vide notification dated 16.1.2013, contained in Annexure- R/1, annexed with the counter affidavit filed on behalf of the Magadh University, the matter is allowed to rest as the petitioner has succeeded in reminding the University authorities, especially the Vice Chancellor as to where he has gone wrong in such decision

WEB COPY NOT OFFICIAL

Patna High Court CWJC No.11220 of 2009 (7) dt.06-02-2013
2/2

making. It is left open to the private respondent to assail the said annexure if he so wants.

The Writ is disposed of.

(Ajay Kumar Tripathi, J)

था। इस त्रुटि को सुधारते हुए कुलपति द्वारा दिनांक-16.01.2013 को अधिसूचना जारी कर डॉ. मिश्रा को डीन पद से हटा दिया गया। चूँकि याचिकाकर्ता की पहल से विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी गलती सुधार ली, इसलिए न्यायालय ने मामले में आगे हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझा। याचिका को निस्तारित (Disposed of) कर दिया गया। उक्त आदेश को धत्ता बताते हुए वर्तमान कुलपति शशि प्रताप शाही ने दिनांक-4.10. 2025 को पुन: डॉक्टर डी.एन. मिश्रा को डीन, फैकेल्टी आफ लॉ बना दिया।

❖ **बिहार वित्तीय नियमावली, विश्वविद्यालय और एक व्यवस्था का आईना :-** शाम ढ़ल चुकी थी। विश्वविद्यालय परिसर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे कुछ छात्र आपस में धीमे स्वर में बात कर रहे थे। कोई परीक्षा शुल्क की चर्चा कर रहा था, कोई ऑनलाइन पोर्टल की अव्यवस्था की, तो कोई यह पूछ रहा था-"हम जो फीस देते हैं, वह जाती कहाँ है?" यही सवाल, धीरे-धीरे, एक कहानी बन गया। यह कहानी किसी एक छात्र की नहीं थी, न किसी एक कॉलेज की। यह कहानी थी मगध विश्वविद्यालय जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान की और उससे भी बड़ी उस व्यवस्था की, जो नियमों से चलने का दावा तो करती है, पर नियमों को कागजों में ही छोड़ देती है। बिहार सरकार ने वर्षों पहले एक नियमावली बनाई थी-नाम था ***बिहार वित्तीय नियमावली।*** इस नियमावली का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था-**"सार्वजनिक धन का उपयोग पारदर्शी हो, हर रुपये का हिसाब हो और कोई भी अधिकारी स्वयं को नियमों से ऊपर न समझे।"**

राज्यपाल सचिवालय, बिहार
बिहार लोक भवन, पटना-800022
पत्रांक-एम.यू.-56/2025-2332/रा.स.(I) दिनांक-16/12/2025
प्रेषक,
डॉ. रॉबर्ट एल. चोंग्थू, भा.प्र.से.
राज्यपाल के प्रधान सचिव
सेवा में,
कुलपति
मगध विश्वविद्यालय
बोधगया
विषय:- विधि संकाय के संकायाध्यक्ष के पद पर डॉ. धर्मा नंद मिश्रा की अवैध नियुक्ति के संबंध में।
महाशय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक डॉ. ब्रज राज कुमार सिंह, प्रति-कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से प्राप्त पत्र दिनांक-17.11.2025 एवं इसकी अनुलग्नकों की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विवादित नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन इस सचिवालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।
अनु-यथा उपर्युक्त।
विश्वासभाजन,
(डॉ. रॉबर्ट एल. चोंग्थू)
राज्यपाल के प्रधान सचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
Magadh University, Bodh Gaya

Notification

Dr. D. N. Mishra, Dean, Faculty of Law, Magadh University, Bodh Gaya is hereby assigned to act as Dean, Faculty of Law till further order after completion of his tenure.

By the order of Hon'ble Vice-Chancellor
Sd/-
Registrar
Magadh University, Bodh Gaya

Memo No. VCS/113/25 Date: 04/10/2025

Copy forwarded for information:
1. Dr. D. N. Mishra, Dean, Faculty of Law, M.U., Bodh Gaya.
2. All Heads, P.G. Deptt. of M.U., Bodh Gaya.
3. All Principal, Constituent Colleges under M.U., Bodh Gaya.
4. Incharge, Meeting Section, M.U., Bodh Gaya.
5. Controller of Examinations, M.U., Bodh Gaya.
6. Secretary/PA to Hon'ble VC/PVC/Registrar, M.U., Bodh Gaya.
7. Nodal Officer (IT), M.U., Bodh Gaya.

Registrar
Magadh University, Bodh Gaya

किताब में सब कुछ लिखा था-कौन पैसा निकाल सकता है, कब निकाला जा सकता है, किस प्रक्रिया से खरीद होगी और किस स्थिति में भुगतान अपराध माना जाएगा।

एक कॉलेज था-पुराना, प्रतिष्ठित। उसके परीक्षा खाते में छात्रों की मेहनत की कमाई जमा होती थी। खाते का एक हस्ताक्षरकर्ता था-प्राचार्य। फिर समय बदला। वही प्राचार्य आगे बढ़कर कुलपति बन गए। कुलपति बनने के बाद भी उसी पुराने खाते से पैसे निकलते रहे-कभी "सेल्फ" में, कभी नकद। बैंक ने अतिरिक्त शुल्क भी काट लिया, मानो खामोशी से कह रहा हो-"यह लेन-देन सामान्य नहीं है।" छात्रों को यह नहीं पता था कि उनके परीक्षा शुल्क से क्या हो रहा है, पर नियम जानते थे और नियम चुप नहीं थे, उन्हें बस पढ़ने वाला चाहिए था।

नई शिक्षा नीति आई। डिजिटल इंडिया की बातें हुईं। विश्वविद्यालय ने कहा-"अब सब कुछ ऑनलाइन होगा।" टेंडर निकला, पर आधा-अधूरा। न वेबसाइट पर, न हर अखबार में। मानो टेंडर नहीं, किसी को इशारा किया गया हो-"आप ही आइए।" काम होने से पहले भुगतान हो गया। काम के सबूत नहीं मिले, पर चेक मिल गया। अगर बिना काम के भुगतान हो सकता है, तो फिर नियम किसके लिए हैं?

एक दिन परिसर में दो नई चमचमाती गाड़ियाँ आईं। काले शीशे, नई सीटें, चमकदार बॉडी। किसी ने पूछा-"टेंडर हुआ था?" "GeM पोर्टल?" "जरूरत का आकलन?" उत्तर में बस खामोशी थी, न भंडार रजिस्टर में नाम, न फाइल में दस्तावेज।

छात्र और शिक्षक मौन। सब कुछ होते हुए भी, परिसर चलता रहा। क्लास लगीं, परीक्षाएँ हुईं, डिग्रियाँ बटी, पर भीतर कुछ टूट रहा था-शिक्षा केवल पाठ्यक्रम नहीं होती। वह आचरण सिखाती है और जब

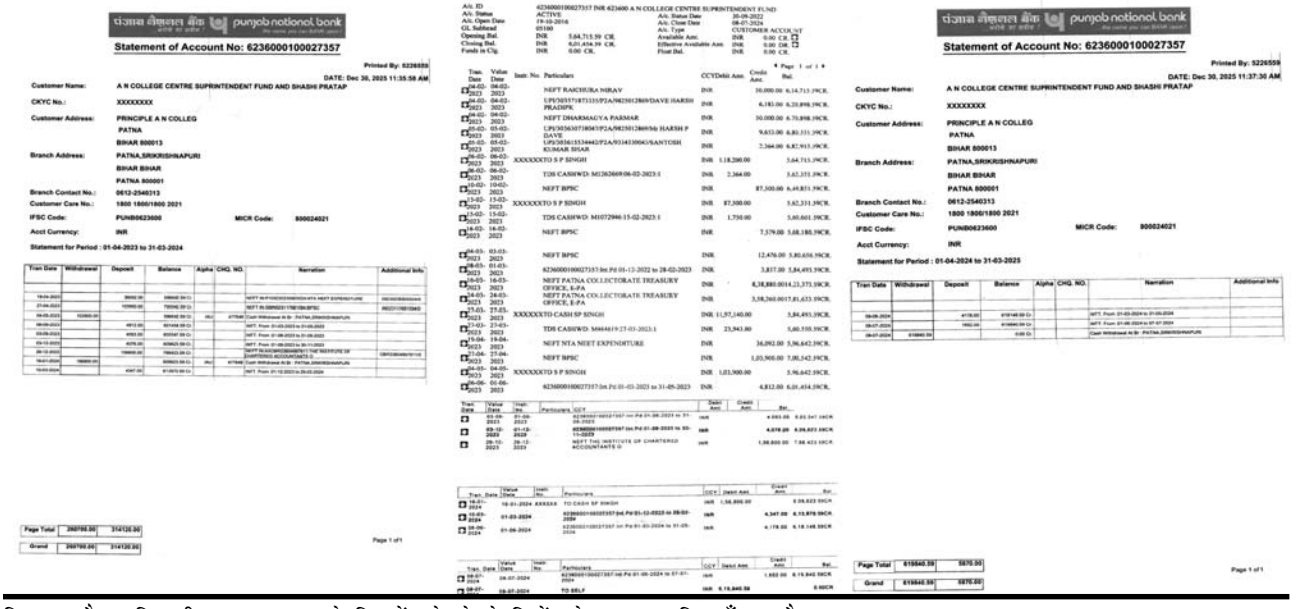

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Statement of Account No: 6236000100027357

Customer Name: A N COLLEGE CENTRE SUPRINTENDENT FUND AND SHASHI PRATAP

CKYC No.: XXXXXXXX

Customer Address: PRINCIPLE A N COLLEG PATNA BIHAR 800013

Branch Address: PATNA,SRIKRISHNAPURI BIHAR BIHAR PATNA 800001

Branch Contact No.: 0612-2540313

Customer Care No.: 1800 1800/1800 2021

IFSC Code: PUNB0623600

MICR Code: 800024021

Acct Currency: INR

Statement for Period : 01-04-2023 to 31-03-2024

Tran Date	Withdrawal	Deposit	Balance	Alpha	CHQ. NO.	Narration	Additional Info

Page 1 of 1

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Statement of Account No: 6236000100027357

Customer Name: A N COLLEGE CENTRE SUPRINTENDENT FUND AND SHASHI PRATAP

CKYC No.: XXXXXXXX

Customer Address: PRINCIPLE A N COLLEG PATNA BIHAR 800013

Branch Address: PATNA,SRIKRISHNAPURI BIHAR BIHAR PATNA 800001

Branch Contact No.: 0612-2540313

Customer Care No.: 1800 1800/1800 2021

IFSC Code: PUNB0623600

MICR Code: 800024021

Acct Currency: INR

Statement for Period : 01-04-2024 to 31-03-2025

Tran Date	Withdrawal	Deposit	Balance	Alpha	CHQ. NO.	Narration	Additional Info

Page 1 of 1

शिक्षक और अधिकारी इस व्यवस्था के नियमों को तोड़ते दिखें, तो छात्र क्या सीखते हैं? राजनीति का साया, फिर सवाल उठे-क्या किसी को संरक्षण मिला? क्या जाँच इसलिए नहीं हुई क्योंकि पद बड़े थे? क्या नियम सिर्फ कमजोरों के लिए हैं?

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरण ने बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह मामला केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की समग्र शैक्षणिक शासन प्रणाली पर पड़ते प्रभावों को उजागर करता है। बिहार सरकार द्वारा लागू बिहार वित्तीय नियमावली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग विधि-सम्मत, मितव्ययी, पारदर्शी और जनहितकारी ढंग से हो। किंतु जब इन्हीं नियमों की अवहेलना शैक्षणिक संस्थानों में होती है, तो उसका दुष्प्रभाव केवल वित्तीय हानि तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह छात्रों के भविष्य, सामाजिक विश्वास और लोकतांत्रिक नैतिकता को भी क्षति पहुँचाता है।

बिहार के प्रतिष्ठित ए.एन. कॉलेज, बोरिंग रोड, पटना में परीक्षाओं के संचालन करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट नंबर -6236000100027357 संचालित है, जिसका आईएफएससी कोड-PUMB0623600 है। इस अकाउंट का संचालन तत्कालीन प्राचार्य श्री शशि प्रताप शाही द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में मगध विश्वविद्यालय गया के कुलपति हैं। इस अकाउंट में कई बार तय नियमों के विरुद्ध सेल्फ और एस.पी. सिंह के द्वारा कैश विड्रोल किया गया, जिसमें पीएनबी द्वारा लगभग 60000 रूपये कैश ट्रांजैक्शन चार्ज भी डिडक्ट किया गया है। यह बात आश्चर्यजनक रूप से इस अकाउंट में परीक्षित है कि श्री शशि प्रताप शाही का दिनांक-13/02/2023 को कुलपति मगध विश्वविद्यालय बनाए जाने के बावजूद भी इस अकाउंट से सेल्फ और एस. पी. सिंह द्वारा 22 लाख 23 हजार 290 रुपए की निकासी हुई है जबकि इस अकाउंट के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी अभी भी कुलपति मगध विश्वविद्यालय,

आरिफ मोहम्मद खान

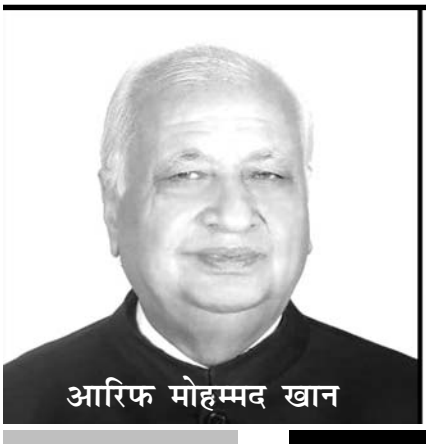

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

पत्रांक-एम.यू.(विविध)-18/2023(पार्ट-1)-1910 /रा.स.(I) दिनांक- 09/10/2025

प्रेषक,

डॉ. नन्दलाल आर्य, भा.प्र.से

राज्यपाल के अपर सचिव

सेवा में,

कुलपति

मगध विश्वविद्यालय

बोधगया

विषयः- कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया पर लगाये गये कतिपय आरोप के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री रविन्द्र नाथ सिंह से प्राप्त परिवाद-पत्र दिनांक-26.06.2025 एवं एतदसंबंधी शपथ-पत्र दिनांक-25.07.2025 तथा इसके अनुलग्नकों की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि परिवाद-पत्र में अंकित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए इस सचिवालय को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

09/10/2025

(डॉ. नन्दलाल आर्य)

राज्यपाल के अपर सचिव

अनु:-यथा उपर्युक्त।

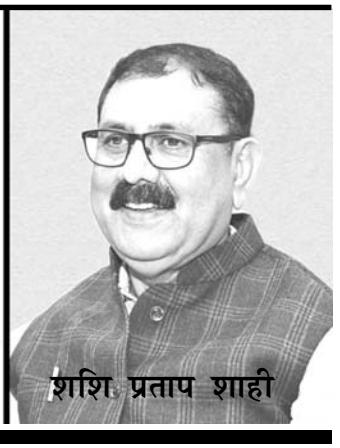

शशि प्रताप शाही

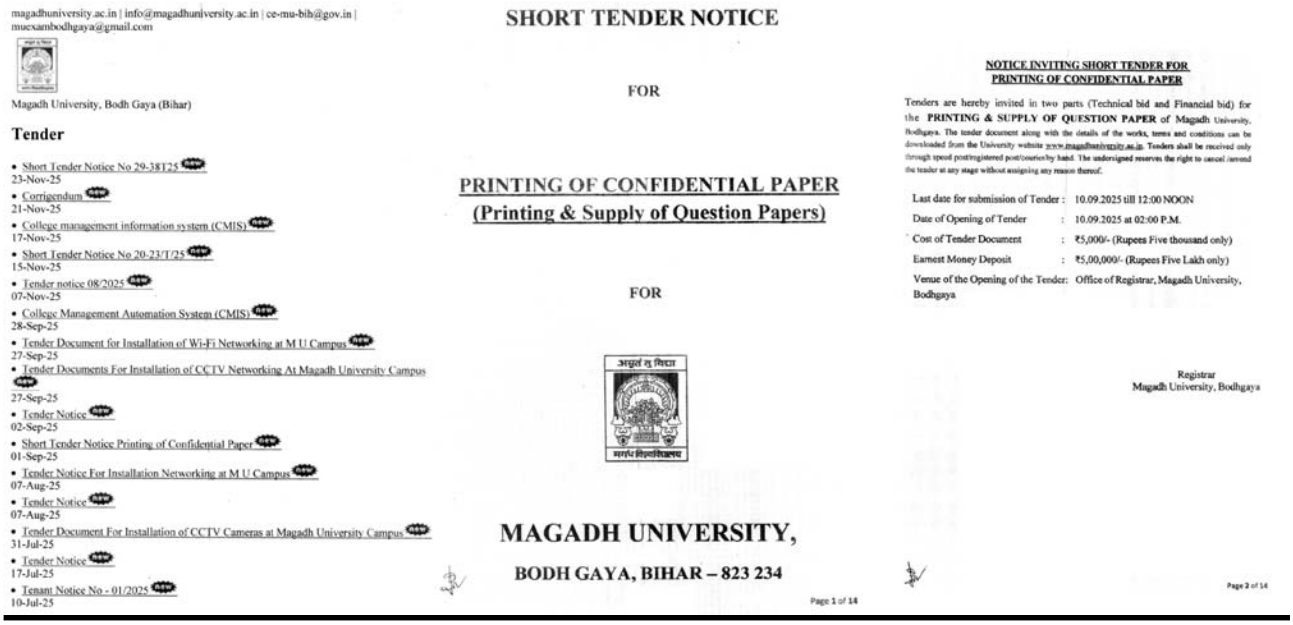

magadhuniversity.ac.in | info@magadhuniversity.ac.in | ce-mu-bih@gov.in | muexambodhgaya@gmail.com

Magadh University, Bodh Gaya (Bihar)

Tender

- Short Tender Notice No 29-38T25 23-Nov-25
- Corrigendum 21-Nov-25
- College management information system (CMIS) 17-Nov-25
- Short Tender Notice No 20-23/T/25 15-Nov-25
- Tender notice 08/2025 07-Nov-25
- College Management Automation System (CMIS) 28-Sep-25
- Tender Document for Installation of Wi-Fi Networking at M U Campus 27-Sep-25
- Tender Documents For Installation of CCTV Networking At Magadh University Campus 27-Sep-25
- Tender Notice 02-Sep-25
- Short Tender Notice Printing of Confidential Paper 01-Sep-25
- Tender Notice For Installation Networking at M U Campus 07-Aug-25
- Tender Notice 07-Aug-25
- Tender Document For Installation of CCTV Cameras at Magadh University Campus 31-Jul-25
- Tender Notice 17-Jul-25
- Tenant Notice No - 01/2025 10-Jul-25

SHORT TENDER NOTICE

FOR

PRINTING OF CONFIDENTIAL PAPER
(Printing & Supply of Question Papers)

FOR

MAGADH UNIVERSITY,

BODH GAYA, BIHAR – 823 234

Page 1 of 14

NOTICE INVITING SHORT TENDER FOR PRINTING OF CONFIDENTIAL PAPER

Tenders are hereby invited in two parts (Technical bid and Financial bid) for the **PRINTING & SUPPLY OF QUESTION PAPER** of Magadh University, Bodhgaya. The tender document along with the details of the works, terms and conditions can be downloaded from the University website www.magadhuniversity.ac.in. Tenders shall be received only through speed post/registered post/courier/by hand. The undersigned reserves the right to cancel /amend the tender at any stage without assigning any reason thereof.

Last date for submission of Tender	:	10.09.2025 till 12:00 NOON
Date of Opening of Tender	:	10.09.2025 at 02:00 P.M.
Cost of Tender Document	:	₹5,000/- (Rupees Five thousand only)
Earnest Money Deposit	:	₹5,00,000/- (Rupees Five Lakh only)
Venue of the Opening of the Tender:		Office of Registrar, Magadh University, Bodhgaya

Registrar
Magadh University, Bodhgaya

Page 2 of 14

गया श्री शशि प्रताप शाही हैं। अब सरकार या राजभवन को यह तय करना है कि श्री शशि प्रताप शाही कुलपति मगध विश्वविद्यालय, गया है या प्राचार्य ए.एन. कॉलेज, बोरिंग रोड, पटना? इन सब विषयों को लेकर तत्कालीन प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण कुमार ने दिनांक-06/08/2024 को आधिकारिक रूप से अपने लेटर हेड पर कुलाधिपति महोदय, बिहार और कुलपति महोदय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना को भी पत्र लिखा है।

कार्यालय मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के अभिलेखों का नमूना लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि इस कार्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत CBCS System लागू होने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था हेतु Short टेंडर का निर्णय लिया गया एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या-R/09/23 दिनांक-19.05.23 द्वारा दैनिक जागरण, गया/पटना, दैनिक भास्कर, गया/पटना, मोर्निंग इंडिया, पटना, सन्मार्ग, गया/पटना में प्रकाशन हेतु पत्र तैयार किया गया, किन्तु दिनांक- 26.05.23 को रद्द कर दिया गया। Short टेंडर आमंत्रण हेतु पत्र सिर्फ दैनिक भास्कर को प्रेषित संचिका में संलग्न पाया गया एवं शेष अन्य समाचार पत्रों को प्रकाशन हेतु कोई भी पत्र संचिका में संलग्न नहीं पाया गया। पुनः विज्ञापन प्रकाशन से सम्बंधित साक्ष्य सिर्फ दैनिक भास्कर के पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर एडिशन में ही संलग्न पाया गया एवं उसका भुगतान हेतु विपत्र संचिका में संलग्न पाया गया, जबकि दिनांक- 26.05.23 को Short टेंडर को रद्द करने का निर्णय एवं इसकी सूचना प्रेषित करने हेतु पत्र DSW/51/23 दिनांक-26.05.23 तैयार किया गया परन्तु न तो इसके प्रेषण से सम्बंधित एवं न ही विज्ञापन प्रकाशन से सम्बंधित कोई साक्ष्य संचिका में संलग्न पायी गई। पुनः पत्र संख्या-DSW/55/2023, दिनांक-31.05.23 द्वारा खुली निविदा प्रकाशन हेतु पत्र The Times of India, पटना, दैनिक जागरण, गया/पटना, दैनिक भास्कर, गया/पटना, मोर्निंग इंडिया, पटना एवं सन्मार्ग, गया/पटना हेतु तैयार किया गया, किन्तु संचिका में पत्रांक संख्या-DSW/56/2023, दिनांक-31.05.23 द्वारा सिर्फ दैनिक भास्कर को ही प्रेषित किया गया परन्तु इसके प्रकाशन से सम्बंधित साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं पाया गया। दैनिक भास्कर द्वारा भी सिर्फ दिनांक-21.05.23 को प्रकाशन से सम्बंधित दावा ही संचिका में संलग्न पाया गया, जबकि Short टेंडर रद्द होने एवं खुली निविदा प्रकाशन से सम्बंधित न तो किसी भी समाचार पत्र द्वारा दावा एवं न ही प्रकाशन से सम्बंधित कोई साक्ष्य सलंग्न पाया गया।

कार्यालय के तकनिकी निविदा से सम्बंधित प्रतिवेदन के अनुसार कुल सात फर्मों द्वारा निविदा में भाग लिया गया तथा वित्तीय निविदा हेतु दो फार्म यथा Micronic Infotech Service PVT. LTD. जयपुर रोड, अजमेर एवं चौधरी प्रिंटिंग प्रेस, पटना ही योग्य पाए गए। चौधरी प्रिंटिंग प्रेस के साथ दर का पुनर्निर्धारण कर उसे L1 घोषित किया गया। दिनांक-22.09.23 को कार्य हेतु एकरारनामा करते हुए दिनांक-27.09.23 को कार्यादेश प्रदान किया गया। एकरारनामा के तहत चयनित एजेंसी को निम्नलिखित कार्य करने थे :-

❖ **Admission Module** :- इसके तहत ऑनलाइन विज्ञापन का प्रकाशन एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना, सम्बंधित कॉलेजों एवं पाठ्यक्रमों के सापेक्ष में पात्रता मापदंड की मान्यता, एकल आवेदन प्रपत्र से विद्यार्थियों को अलग-अलग कॉलेज एवं पाठ्यक्रम में आवेदन करने में सुविधा प्रदान करना, शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे से जहाँ विद्यार्थियों द्वारा सीधे विश्वविद्यालय के खाते में राशि का हस्तांतरण, योग्यता सूची विश्वविद्यालय के नियमों एवं आरक्षण नियमों के तहत, ऑनलाइन रिक्तियों को प्रदर्शित करना एवं अन्य विश्वविद्यालय के अनुसार प्रतिवेदनों को तैयार करना जैसे आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की विषयवार/पाठ्यक्रमवार विवरणी, शुल्क प्राप्ति एवं अन्य प्रतिवेदन :-

☞ **Registration Module** :- विद्यार्थियों के लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा प्रवेशित छात्र का यूनिक पंजीकरण आईडी से पंजीकरण, शुल्क का पेमेंट गेटवे से सीधा विश्वविद्यालय के खाते में भुगतान एवं विभिन्न प्रकार के MIS प्रतिवेदन तैयार करना।

☞ **Pre-Examination Module** :- विभिन्न कोर्स के लिए विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर परीक्षा प्रपत्र को डिजाईन एवं विकसित करना, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, परीक्षा शुल्क पेमेंट गेटवे से प्राप्त करना एवं उसका रसीद तैयार करना, परीक्षा केन्द्रों का डायनामिक आधार पर चयन, अटेंडेंस शीट/एब्सेंटी शीट प्रत्येक केंद्र के लिए तैयार करना, उपस्तिथि पंजी, रोल शीट, डिस्पैच मेमो विश्वविद्यालय को तय

समय पर प्रदान करना एवं पूर्ण MIS प्रतिवेदन तैयार करना।

☞ **Post Examination Module** :- सभी प्रश्न पत्रों को प्राप्त करना एवं उसका छंटाई, OMR आंकड़ों का निर्माण एवं स्कैनिंग, अंकपत्र एवं प्रोविजिनल सर्टिफिकेट एवं डिग्री सर्टिफिकेट की आपूर्ति।

लेखा परीक्षा क्रम में आगे ज्ञात हुआ की उक्त कार्य को करने हेतु निम्न प्रकार से दर का एकारानमा चयनित एजेंसी के साथ किया गया:-

क्र०सं०	विवरणी	दर	राशि (रूपए में)
01	Design and Develop, Implement and Support, for implementation of online processing Examination System.	Lumpsum	6,30,000/-
02	AMC for 2nd Years	In	25%
	onwards	percentage of selling price	
03	Complete work related to the Admission Process work.	Rate per student	37/-
04	Complete work related to the Registration Process work.	Rate per student	37/-
05	Complete work related to the Pre-Examination process work.	Rate per student	65/-
06	Complete work related to the Post Examination and Result process work	Rate per student	69/-
07	Paper size above A3 size	Rate per page	27.25/-
08	Paper size A3	Rate per page	6.85/-
09	Paper size/A4 size	Rate per page	3/-
10	Data entry of each students record of referral fields	Rate per record	7/-
11	Unbinding and	Rate per	102/-
	binding of T.R. register	register	
12	Supply of marks sheet with at least 7 security features on 105 GSM parchment paper	Rate per mark sheet	9.50/-
13	Supply of provisional degree certificate with at least 7 security features on 275 GSM Ivory Paper	Rate per degree	21/-
14	Supply of degree certificate with 13 security features on 175 micro non-tearable paper	Rate per degree	42/-

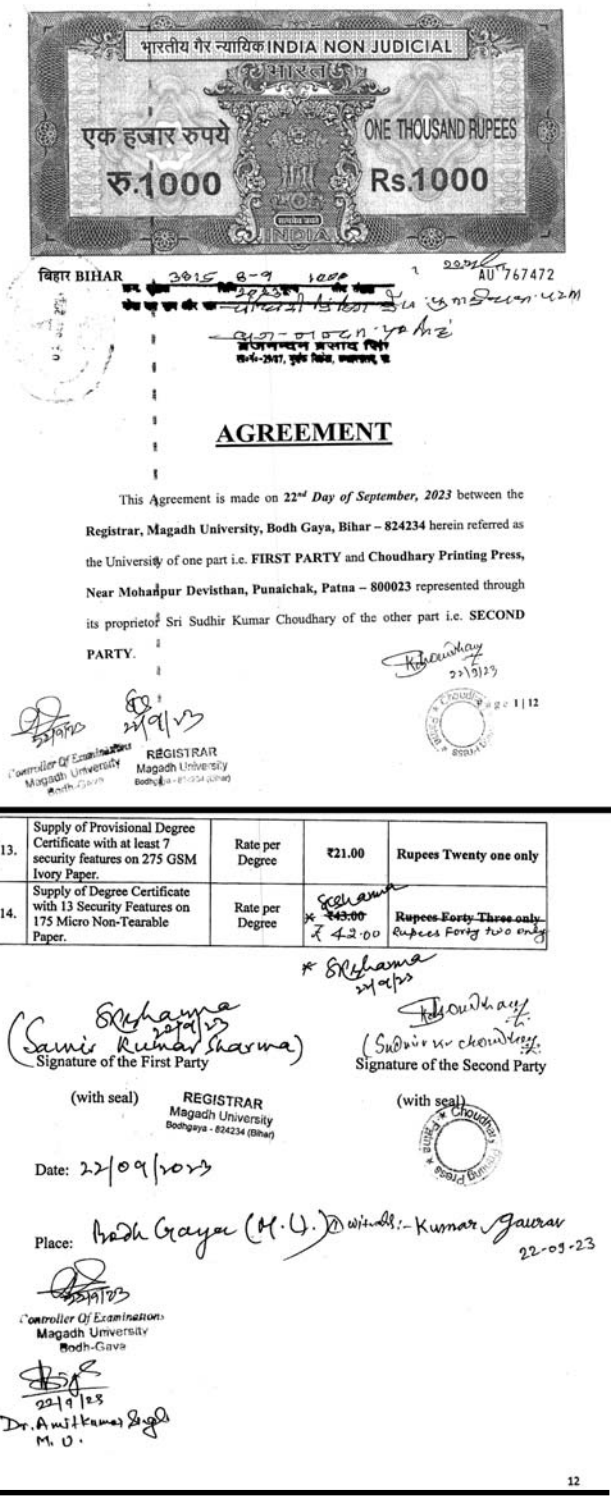

बिहार BIHAR AU 767472

AGREEMENT

This Agreement is made on 22nd *Day of September, 2023* between the **Registrar, Magadh University, Bodh Gaya, Bihar – 824234** herein referred as the University of one part i.e. **FIRST PARTY** and **Choudhary Printing Press, Near Mohanpur Devisthan, Punaichak, Patna – 800023** represented through its proprietor Sri Sudhir Kumar Choudhary of the other part i.e. **SECOND PARTY**.

Controller Of Examinations, Magadh University, Bodh-Gaya — REGISTRAR, Magadh University

Page 1|12

13.	Supply of Provisional Degree Certificate with at least 7 security features on 275 GSM Ivory Paper.	Rate per Degree	₹21.00	**Rupees Twenty one only**
14.	Supply of Degree Certificate with 13 Security Features on 175 Micro Non-Tearable Paper.	Rate per Degree	~~₹43.00~~ ₹ 42.00	~~**Rupees Forty Three only**~~ Rupees Forty two only

(Samir Kumar Sharma) Signature of the First Party (with seal) REGISTRAR Magadh University Bodhgaya - 824234 (Bihar)

(Sudhir kr choudhary) Signature of the Second Party (with seal)

Date: 22/09/2023

Place: Bodh Gaya (M.U.) witness:- Kumar Gaurav 22-09-23

Controller Of Examinations, Magadh University, Bodh-Gaya

Dr. Amit Kumar Singh M.U.

12

लेखा परीक्षा क्रम में आगे ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय ने नए CBCS कोर्स में नामांकन एवं पंजीकरण हेतु सभी प्राचार्यों को ज्ञापांक संख्या-DSW/49/23, दिनांक-22.05.23 को यह निर्देश प्रदान किया कि सभी नामांकन एवं पंजीकरण दिनांक-20.05.23 से प्रारंभ कर दिनांक-30.06.23 तक पूर्ण कर लें एवं दिनांक-04.07.23 से कक्षा शुरू कर दें। इस कोर्स हेतु परीक्षा का समय निर्धारण भी दिनांक-21.11.23 से 15.12.23

मनीष कुमार
समाजिक कार्यकर्ता
आर टी आई कार्यकर्ता

सत्यमेव जयते

कोपरेटिव बैंक के पीछे, गली नं0-03 के आखिर में महाराजा हाता, आरा, भोजपुर – 802301
Mob – 8757737808
Email – mannishkumar08@gmail.com

पत्रांक – JAN/SKS/26 दिनांक – 14/01/2025

सेवा में
माननीय कुलाधिपति,
लोक भवन, पटना।
माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार, पटना।
✓माननीय शिक्षा मंत्री,
बिहार सरकार, पटना।

वितरण शाखा 16 JAN 2026 शिक्षा विभाग 14.01.2026

विषय :- भष्टाचार में संलिप्त मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के कुलपति प्रो शशि प्रताप शाही द्वारा एन कालेज पटना के पी.एन.बी. अकाउंट से लगभग 25 लाख रुपए की अवैध निकासी एवं चौधरी प्रिंटिंग प्रेस से मिलकर करोड़ों रुपए के घोटलों की जांच कर/कराने हेतु समुचित विधिसम्मत निर्णय लेने के संबंध में।

प्रसंग :- राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–1910 दिनांक – 09.10.2025 (छायाप्रति संलग्न), पी.एन.बी. एकाउंट के छायाप्रति संलग्न, चौधरी प्रिंटिंग प्रेस की एग्रीमेंट पेपर की छायाप्रति संलग्न के क्रम में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रसंग में राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक- **1910 दिनांक –09.10.2025** (छायाप्रति संलग्न) में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है जो इस तथ्य का द्योतक है कि **कुलपति, मगध विश्वविद्यालय** द्वारा किया गया **भष्टाचार"जांच-योग्य" है।**

आलोच्यविषयांकित मामले में**माननीय कुलाधिपति महोदय,** को संज्ञानित करना है कि एन कालेज, **बोरिंगरोड, पटना में परीक्षाओं के संचालन करने के लिए "पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट नंबर – 6236000100027357** संचालित है जिसका **आईएफ एस सी कोड- pmbo623600** है इस अकाउंट से तत्कालीन प्राचार्य प्रो शशि प्रताप शाही द्वारा किया जा रहा है जो वर्तमान में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर आसीन हैं। इस अकाउंट से अनेकों बार नियम विरुद्ध सेल्फ और कैशनिकाशी स्वयं कुलपति के द्वारा किया गया है। जिसमें पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लगभग **-60,000** कैशट्रांजेक्शनचार्ज डिडक्ट किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

प्रो. शशि प्रताप शाही, दिनांक – 13.02.2023 को मगध विश्वविद्यालय, के कुलपति बनाएं जाने के बाद भी उपरोक्त अकाउंट से सेल्फशशि प्रताप शाही द्वारा **22 लाख 23290 रूपए की निकासी किया गया** (**छायाप्रति संलग्न**) जो प्रशासनिक भष्टाचार के साथ साथवित्तीय अनियमितता भी है।

कुलपतिने मगध विश्वविद्यालय के प्रिंटिंग प्रेस का कार्य करने काले चौधरी प्रिंटिंग प्रेस से मिलकर 30 / कमीशन लेकर छात्रों से वसूली (governmentso governmententsp@ barodampay) के नाम पर

मनीष कुमार
समाजिक कार्यकर्ता
आर टी आई कार्यकर्ता

सत्यमेव जयते

कोपरेटिव बैंक के पीछे, गली नं0-03 के आखिर में महाराजा हाता, आरा, भोजपुर – 802301
Mob – 8757737808
Email – mannishkumar08@gmail.com

पत्रांक – दिनांक –

करोड़ों रुपया "चौधरी प्रिंटिंग प्रेस" को भेजा जा रहा है जो गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला है साथ ही यह अंकित करना है कि चौधरी प्रिंटिंग प्रेस का अनुबंध 22.09.2023 को एक साल के लिए हुआ था। आश्चर्यजनक यह है कि कुलपति, द्वारा बगैरनिविदा कराए अदिनांककार्य लिया जा रहा है। चर्चा आम है कि इस कंपनी में कुलपति के पुत्र वरूण कुमार शाही भी पार्टनर है।

इसके अतिरिक्त कुलपति के facebookदेखने से यह पता चलता है कि ये **"शिक्षाविद"** कम और राजनेता ज्यादा दिखतें हैं। यह मामला **"लोक-हित"** से संबंध रखता है और यह संघर्ष भष्टाचार के विरुद्ध है जिसे सार्वजनिक करना अतिआवश्यक ही नहीं परिहार्य भी है **प्रशासनिक सुचिताएवं पारदर्शिता एक पवित्र कार्य है जोड़ तोड़ करके कुलपति जैसे गरिमामय पद पर आसीन अथवा देना पूर्णतः गलत एवं अवैधानिक है। इस पूरे प्रकरण में कुलपति की भूमिका संदिग्ध है जो जांच के क्रम में कदाचित दृष्टिगोचर होगा** अंत में विषयगतआलोच्य प्रसंग को इन पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं कि :-

"जब गति प्रबल पैरोंमें भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा," आज मेरे सामने रास्ता इतना पड़ा, जब-तक मंजिल न पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है, चलना मेरा काम है, चलना मेरा काम है..."।

अतः माननीय कुलाधिपति महोदय से आग्रह है कि उपरोक्त विषयगतमामले में संलग्न कागजातों को दृष्टिपथ में रखते हुए एक गंभीर जांच कर/ कराकर वित्तीय वित्तीय अनुशासनहीनता/अनियमितता के उत्तरदायी कुलपति,कुलसचिव, वित्तीय परामर्शी, वित पदाधिकारी एवं संबंधित सहायकों के विरुद्ध समुचित विधिसम्मत कार्रवाई करने की अविलंब कृपा की जाए।

सादर प्रेषित
अनुलग्नक -यथोक्

आवेदक
मनीष कुमार

तक निर्धारित कर दी गई थी। सभी नामांकन एवं पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर परीक्षा भी दिनांक-26.12.23 से 07.01.24 के अवधि में पूर्ण कर ली गई।

लेखा परीक्षा क्रम में आगे ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही एक और एजेंसी CSC Data System (P) LTD द्वारा भी कार्य कर उसे भुगतान किया गया था एवं उसके विपत्रों के जाँच में यह पाया गया कि उक्त एजेंसी द्वारा Pre Phase Eñamination Processing work के लिए प्रति छात्र रु०18/- एवं Post Phase हेतु प्रति छात्र रु० 21-24/- की दर से भुगतान प्राप्त किया। अर्थात् सामान वित्तीय वर्ष में ही दो अलग-अलग एजेंसी द्वारा एक ही काम के दर में 361 प्रतिशत की वृद्धि Pre Phase Examination Processing work में एवं 325 प्रतिशत की वृद्धि की दर से कार्य कराया जा रहा था।

आगे लेखा परीक्षा क्रम में निम्न लेखा परीक्षा अवलोकन पाया गया :-

❖ विश्वविद्यालय के संचिका संख्या-Nil, दिनांक-29.09.23 के द्वारा यह स्पष्ट है की चयनित एजेंसी के साथ एकरारनामा 22.09.23 एवं कार्यादेश 27.09.23 को प्रदान किया गया, जबकि CBCS प्रणाली के अंतर्गत सत्र 2023-27 के छात्रों का नामांकन एजेंसी के कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व ही कर लिया गया था। एकरारनामा के अनुसार चयनित एजेंसी को ऑनलाइन विज्ञापन का प्रकाशन एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना, सम्बंधित कॉलेजों एवं पाठ्यक्रमों के सापेक्ष में पात्रता मापदंड की मान्यता, एकल आवेदन प्रपत्र से विद्यार्थियों को अलग-अलग कॉलेज एवं पाठ्यक्रम में आवेदन करने में सुविधा प्रदान करना, शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे से जहाँ विद्यार्थियों द्वारा सीधे विश्वविद्यालय के खाते में राशि का हस्तांतरण, योग्यता सूची, विश्वविद्यालय के नियमों एवं आरक्षण नियमों के तहत, ऑनलाइन रिक्तियों को प्रदर्शित करना एवं अन्य विश्वविद्यालय के अनुसार प्रतिवेदनों को तैयार करना, जैसे- आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की विषयवार/पाठ्यक्रमवार विवरणी, शुल्क प्राप्ति एवं अन्य प्रतिवेदन का कार्य करने के बाद ही भुगतान करना था, किन्तु एजेंसी को विश्वविद्यालय द्वारा बिना कोई नामांकन का कार्य कराये हुए भी उसे नामांकन हेतु प्रति छात्र रु० 37/- की दर से प्रथम कुल दावा की गई राशी का 90 प्रतिशत अर्थात् रु० 32,07,238/- का GST एवं IT की राशि काटकर रु० 31,41,784/- का भुगतान किया गया एवं बाद में शेष 10 प्रतिशत अर्थात् रु० 9,19,594/- में GST एवं IT की कटौती करते हुए रु० 9,08,390/- का भुगतान किया गया। अर्थात् बिना कोई कार्य संपन्न कराये हुए भी चयनित एजेंसी को विश्वविद्यालय द्वारा कुल रु० 41,92,286/- का अदेय भुगतान किया गया।

☞ विश्वविद्यालय के संचिका CEO/41/24, दिनांक-06.02.24 द्वारा यह स्पष्ट किया गया की चयनित एजेंसी द्वारा दिनांक-27.01.24 तक परीक्षा प्रवेश पत्र से सम्बंधित किसी भी प्रकार का डाटा शाखा को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं परीक्षा शाखा के अभिलेखों से यह उल्लेखित हुआ कि ज्ञान बुद्ध गुरुकुल कॉलेज, डोभी, गया एवं सुरेन्द्र प्रसाद यादव कॉलेज, गया द्वारा विश्वविद्यालय को पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी गई थी, अर्थात् पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क भी कॉलेज द्वारा अपने स्तर से किया गया न की चयनित एजेंसी द्वारा, परन्तु उसके बाद भी विश्वविदयालय द्वारा पंजीकरण के कार्य हेतु रु० 30,82,211/- एवं Pre-Exam कार्य हेतु रु० 54,14,695/- का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जो की अदेय था।

☞ विश्वविद्यालय एवं चयनित एजेंसी के साथ एकरारनामा के Post Examination Module में ही Marksheet, provisional

certificate एवं डिग्री सर्टिफिकेट की आपूर्ति के दर के साथ रु० 69/- का दर अंकित किया गया था, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उसी एकरारनामा में पुन: क्रम संख्या-12 में marksheet के आपूर्ति हेतु अलग से रु० 9 से 50/-, Provisional डिग्री सर्टिफिकेट हेतु रु० 21/- एवं डिग्री सर्टिफिकेट की आपूर्ति हेतु रु० 42/- की दर स्वीकृत की गई, अर्थात् एक ही कार्य के लिए दो अलग-अलग भुगतान हेतु दर स्वीकृत की गई।

☞ विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा निष्पादन हेतु राष्टीय समाचार पत्र में प्रकाशन न कर सिर्फ एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर एडिशन में ही पत्रांक संख्या-DSW/56/2023, दिनांक-31.05.23 द्वारा प्रेषित किया गया, परन्तु इसके प्रकाशन से सम्बंधित साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं पाया गया। वित्तीय नियमावली के अनुसार इसका प्रकाशन विभाग के पोर्टल पर भी करना था, जबकि इसे विभाग के पोर्टल पर प्रकाशित नहीं किया गया, जिसके कारण इसमें भाग लेने वालों के लिए पूरे भारत में एजेंसी को सामान अवसर प्राप्त नहीं हो सका एवं इससे खुली एवं निष्पक्ष निविदा निष्पादन संपन्न नहीं हो सकी।

☞ एकरारनामा की शर्तों के अनुसार चयनित एजेंसी को MIS प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध करनी थी, जबकि लेखा परीक्षा क्रम में ऐसा कोई भी प्रतिवेदन कार्यालय के संचिका में संलग्न नहीं पाया गया, जिससे यह प्रतीत हो सके की उक्त एजेंसी ने सभी कार्य संपन्न कर लिया था एवं कार्य के अनुसार ही भुगतान किया गया।

☞ निविदा के तकनिकी निविदा में चयनित एजेंसी द्वारा समर्पित बैंक अकाउंट में खाता संख्या-59209835492012, IFSC-HDFC0000235, चालू खाता दर्शाया गया था, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान इस खाते में न कर उसे खाता संख्या-2968002100010018, IFSC-PUNB0296800 में किया गया, जबकि कार्यालय के संचिका में अलग खाते में भुगतान सम्बंधी कोई भी आधार स्पष्ट नहीं किया गया था।

☞ कार्यालय द्वारा CBCS कोर्स के नामांकन, पंजीकरण, परीक्षा शुल्क आदि का छात्र से सीधा विश्वविद्यालय के खाता में राशि के हस्तातरण से सम्बंधित कोई भी प्रतिवेदन या राशि की विवरणी उपलब्ध नहीं है एवं न ही चयनित एजेंसी द्वारा ही इसका कोई प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित किया गया है।

☞ विश्वविद्यालय द्वारा सामान कार्य के लिए सामान वर्ष में एक ही कार्य के लिए अलग-अलग दर का निर्धारण किया गया एवं दोनों दर में 361 एवं 325 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एकरारनामा किया गया, अर्थात् एजेंसी को अधिक दर से भुगतान हेतु चयन किया गया।

☞ **लेखा परीक्षा निष्कर्ष :-** उपरोक्त लेखा परीक्षा अवलोकन के आधार पर यह स्पष्ट है की विश्वविद्यालय द्वारा निविदा का अनियमित तरीके से निष्पादन कर चयनित एजेंसी के साथ न सिर्फ बढ़े हुए दर से बल्कि एक ही कार्य के लिए अलग-अलग भुगतान दर को स्वीकृत

GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
RAJ BHAVAN, PATNA-800022

NOTIFICATION

Dated- 13.02.2023

No.BSU(VC MU)- 11/2022- 223 /GS(I)- In exercise of powers conferred under sub-section (2) of Section 10 of Bihar State Universities Act, 1976, (as amended up-to-date) and after effective and meaningful consultation with the State Government on the panel submitted by the Search Committee, constituted for recommending panel of names, for the post of Vice-Chancellor, Magadh University, Bodh Gaya the Hon'ble Chancellor has been pleased to appoint **Prof. Shashi Pratap Shahi** as Vice-Chancellor of Magadh University, Bodh Gaya for a period of three years from the date he assumes the charge of the Office.

By the order of the Hon'ble Chancellor
Sd/-
(Robert L. Chongthu)
Principal Secretary to H.E. the Chancellor
Bihar

Memo No.- BSU(VC MU)- 11/2022- 223/GS(I) Dated- 13.02.2023

Copy forwarded for information and necessary action to:-

(1) **Prof. Shashi Pratap Shahi,** Shashi regency,near pani tanki, mahesh Nagar, phulwari, Patna-800024 e-mail- **profshashi@gmail.com**
(2) **The Chairman**, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002
(3) **The Principal Secretary** to Chief Minister of Bihar.
(4) **The Principal Secretary**, Department of Education, Govt. of Bihar, Patna.
(5) **The Registrar**, Magadh University, Bodh Gaya.
(6) **All Vice-Chancellors**, Universities of Bihar.
(7) **PS to Governor / PS to Principal Secretary / PRO** / All concerned Officers / **Protocol Officer** / PBX / Governor's Secretariat, Bihar, Patna.
(8) **Shri Rohan Mishra**, Assistant Director (IT) for uploading on Website of Raj Bhavan, Patna / **Concerned Assistant,** University Section, Raj Bhavan, Patna.

13.2.2023
(Robert L. Chongthu)
Principal Secretary to H.E. the Chancellor

AKANKSHA.NOTIFICATION/2021

A.N. COLLEGE, PATNA
Patliputra University, Patna

Office of the Principal — Mob. No.: 8986324667

Ref. G-794/24 — Date: 6.8.24.

To,
The Hon'ble Chancellor
Universities of Bihar (Patliputra University)
Patna

Sub :- Information of Fraud and Financial Misappropriation Committed by Prof(Dr.) Shashi Pratap Shahi, Vice Chancellor, Magadh University, Bodh Gaya.

Respected Honourable Chancellor,

I am writing to bring your kind attention that I have been transferred to the post of Principal, A.N College, Patna vide PPU order No :- R/PPU/314/2023, Dated 14/02/2023. From 14/02/2023 I am regularly working as Principal in A.N. College, Patna. Prof.(Dr.) Shashi Pratap Shahi was former Principal of A.N. College, Patna just before me.

After my joining as Principal, A.N College, Patna, a CS Account has been opened for hurdle free examinations by me at Punjab National Bank, Shri Krishna Puri Branch, Patna, bearing A/C No - 6236000100037521, IFSC- PUNB0623600, Namely- CS AN COLLEGE PATNA AND PRAVIN KUMAR. I have provided the utilisation Certificate to the concerned institution after completion of the examination. (Statement of Bank Account No - 6236000100037521 is hereby enclosed)

I have just come to know that a CS Account was opened in Punjab National Bank, Shri Krishna Puri Branch, Patna, bearing A/C No - 6236000100027357, IFSC- PUNB0623600, Namely- AN COLLEGE CENTRE SUPRINTENDENT FUND AND SHASHI PRATAP SHAHI, Now Prof(Dr.) Shashi Pratap Shahi is presently working as Vice Chancellor of Magadh University, Bodh Gaya.

College's PAN has been used to operate both CS account :- A/C No - 6236000100037521 and A/C No - 6236000100027357. Authorise person to operate CS Account is Principal-cum-Centre Superintendent of the College.

Contd. On Page 2.......

A.N. COLLEGE, PATNA
Patliputra University, Patna

Office of the Principal — Mob. No.: 8986324667

Ref. — Date:

Page 02

A serious matter of fraud and financial misappropriation committed by Prof.(Dr.) Shashi Pratap Shahi, the former Principal of A.N. College, Patna. Prof. Shahi misrepresented himself as the authorized signatory for the Centre Superintendent's (CS) account of the College and withdrew a significant amount of money without the knowledge or consent of the current CS or college administration. After my taken charge on 14/02/2023, Total amount of Rs. 21,90,873.59 (Rs. Twenty Lakh Ninety Thousand Eight Hundred Seventy Three and Fifty Nine Paise) has been illegally withdrawn by Prof. Shahi from 15/02/2023 to 06/07/2024 from the same account (Statement of Bank Account No - 6236000100027357 is hereby enclosed).

This fraudulent activity is a clear violation of financial protocols and a serious breach of trust. Prof. Shahi's misrepresentation and abuse of his former position have caused significant financial harm to our college, and I am deeply concerned about the potential magnitude of the loss.

I request that you take the following steps :-

1. Institute a high-level inquiry into this matter to determine the extent of the fraud and identify those responsible.
2. Consider taking appropriate disciplinary action against Mr. Shahi and any other individuals found to be involved in this fraudulent activity.
3. Review and strengthen the college's financial protocols to prevent such incidents from occurring in the future.

I would appreciate your prompt attention to this matter, and I am available to provide any additional information or support necessary to investigate and resolve this issue.

With Regards.

Enclosure-1-9 pages

Yours faithfully,
Prof(Dr.) Prujila Kumar
Principal-cum- Centre Superintendent
A.N. College, Patna

Office of the Principal — Mob. No.: 8986324667

Ref. G-795/24. — Date: 6.8.24

To,
The Hon'ble Vice Chancellor
Patliputra University, Patna
Patna

Sub :- Information of Fraud and Financial Misappropriation Committed by Prof(Dr.) Shashi Pratap Shahi, Vice Chancellor, Magadh University, Bodh Gaya.

Respected Honourable Chancellor,

I am writing to bring your kind attention that I have been transferred to the post of Principal, A.N College, Patna vide PPU order No :- R/PPU/314/2023, Dated 14/02/2023. From 14/02/2023 I am regularly working as Principal in A.N. College, Patna. Prof.(Dr.) Shashi Pratap Shahi was former Principal of A.N. College, Patna just before me.

After my joining as Principal, A.N College, Patna, a CS Account has been opened for hurdle free examinations by me at Punjab National Bank, Shri Krishna Puri Branch, Patna, bearing A/C No - 6236000100037521, IFSC- PUNB0623600, Namely- CS AN COLLEGE PATNA AND PRAVIN KUMAR. I have provided the utilisation Certificate to the concerned institution after completion of the examination. (Statement of Bank Account No - 6236000100037521 is hereby enclosed)

I have just come to know that a CS Account was opened in Punjab National Bank, Shri Krishna Puri Branch, Patna, bearing A/C No - 6236000100027357, IFSC- PUNB0623600, Namely- AN COLLEGE CENTRE SUPRINTENDENT FUND AND SHASHI PRATAP SHAHI, Now Prof(Dr.) Shashi Pratap Shahi is presently working as Vice Chancellor of Magadh University, Bodh Gaya.

College's PAN has been used to operate both CS account :- A/C No - 6236000100037521 and A/C No - 6236000100027357. Authorise person to operat CS Account is Principal-cum-Centre Superintendent of the College.

Contd. On Page 2.......

0612-2540482
principal@ancpatna.ac.in
principalancollege@gmail.com
www.ancpatna.ac.in

A.N. COLLEGE, PATNA
Patliputra University, Patna

Office of the Principal — Mob. No.: 8986324667

Ref. — Date:

Page 02

A serious matter of fraud and financial misappropriation committed by Prof.(Dr.) Shashi Pratap Shahi, the former Principal of A.N. College, Patna. Prof. Shahi misrepresented himself as the authorized signatory for the Centre Superintendent's (CS) account of the College and withdrew a significant amount of money without the knowledge or consent of the current CS or college administration. After my taken charge on 14/02/2023, Total amount of Rs. 21,90,873.59 (Rs. Twenty Lakh Ninety Thousand Eight Hundred Seventy Three and Fifty Nine Paise) has been illegally withdrawn by Prof. Shahi from 15/02/2023 to 06/07/2024 from the same account (Statement of Bank Account No - 6236000100027357 is hereby enclosed).

This fraudulent activity is a clear violation of financial protocols and a serious breach of trust. Prof. Shahi's misrepresentation and abuse of his former position have caused significant financial harm to our college, and I am deeply concerned about the potential magnitude of the loss.

I request that you take the following steps :-

1. Institute a high-level inquiry into this matter to determine the extent of the fraud and identify those responsible.
2. Consider taking appropriate disciplinary action against Mr. Shahi and any other individuals found to be involved in this fraudulent activity.
3. Review and strengthen the college's financial protocols to prevent such incidents from occurring in the future.

I would appreciate your prompt attention to this matter, and I am available to provide any additional information or support necessary to investigate and resolve this issue.

With Regards.

Enclosure-1-9 pages

Yours faithfully,
Prof(Dr.) Prujila Kumar
Principal-cum- Centre Superintendent
A.N. College, Patna

0612-2540482
principal@ancpatna.ac.in
principalancollege@gmail.com
www.ancpatna.ac.in

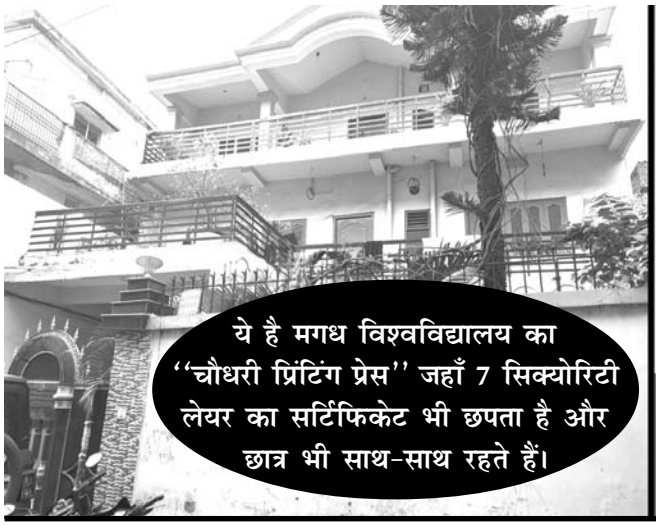

किया गया। साथ ही चयनित एजेंसी को वैसे अवधि का भी भुगतान किया गया, जिस अवधि में उसके साथ एकरारनामा भी नहीं किया गया था, अर्थात् कार्य पूरा होने के पश्चात् जैसे-नामांकन का कार्य होने के पश्चात् ही एकरारनामा किया गया एवं बिना नामांकन, पंजीकरण एवं अन्य कार्य किये हुए भी एजेंसी को अदेय भुगतान 1,26,89,192/- रुपये किया गया तथा भुगतान भी चयनित एजेंसी द्वारा तकनिकी निविदा में दर्शाए गए बैंक खाते से अलग खाते में बिना किसी आधार के किया गया। यह स्पष्ट है की विश्वविद्यालय द्वारा एजेंसी को अनुचित लाभ पहुँचाया गया एवं उसे अदेय भुगतान किया गया।

❖ **अनियमित क्रय 43,98,899/- रूपये।**

नियम 131छ-प्रस्ताव (बोली) आमंत्रित कर वस्तुओं की खरीद-विभाग नियम 131ग, 131, 131ङ (1) के अन्तर्गत आच्छादित मामलों को छोड़कर नियम 128 में वर्णित शक्ति के अधीन मानक तरीके से प्रस्ताव आमंत्रित कर वस्तुओं की अभिप्राप्ति निम्नवत् करेगा :-
(i) विज्ञापित निविदा पूछताछ (ii) सीमित निविदा पूछताछ (iii) एकल निविदा पूछताछ।

नियम 131 ज-विज्ञापित निविदा पूछताछ- (i) नियम 131झ तथा 131ञ के अन्तर्गत समावेशित अपवादों को छोड़कर रुपये 25,00,000.00 (पच्चीस लाख रुपये) एवं इससे अधिक आकलित मूल्य की सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रण का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों को विज्ञापन महानिदेशक, वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित इण्डियन ट्रेंड जर्नल (आई0 टी0 जे0) तथा कम-से-कम एक राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक प्रसार वाली दैनिक पत्र में किया जाना चाहिए।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-9230, दिनांक-27.11.2017 के द्वारा बिहार वित्त नियमावली 1950 के नियम 30 के उपनियम (XX) को प्रतिस्थापित करते हुये यह उल्लेख किया गया है कि GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति अनिवार्य रूप से सभी विभागों द्वारा, आवश्यकतानुसार की जायेगी। साथ ही वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 1407 दिनांक 22.02.2018 द्वारा सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति अनिवार्य रूप से करने हेतु दिनांक 01.04.2018 की तिथि नियत की गयी थी।

कार्यालय मगध विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि इस कार्यालय द्वारा परीक्षा मद की राशि से दिनांक-10.11.23 को दो गाड़ियों का क्रय किया गया, जिस पर रु० 24,45,440/- एवं रु० 19,53,459/- अर्थात् कुल रु० 43,98,899/- का भुगतान A.P.R. ऑटोमोबाइल, गया को किया गया। उक्त गाड़ियों के क्रय हेतु विश्वविद्यालय द्वारा न तो कोई निविदा का प्रकाशन किया गया एवं न ही GeM पोर्टल पर उपलब्ध सामग्रियों की अधिप्राप्ति की गई। आगे लेखा परीक्षा क्रम में विश्वविद्यालय में उपलब्ध कुल गाड़ियों की सूची की मांग करने एवं मौखिक रूप से भी कई बार आग्रह करने पर विश्वविद्यालय द्वारा मौखिक रूप से बताया गया की इस विश्वविद्यालय में संचालित गाड़ियों की सूची एवं उसका संबंधन से सम्बंधित कोई भी संचिका तैयार नहीं की गई है एवं न ही कोई प्रतिवेदन उपलब्ध है।

लेखा परीक्षा क्रम में पाया गया कि गाड़ियों के क्रय हेतु न तो कोई आंकलन किया गया एवं न ही विश्वविद्यालय से कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया एवं ये दोनों गाड़ियाँ क्रय के पश्चात् भी विश्वविद्यालय के भंडार पंजी में कोई इन्द्राज नहीं किया एवं क्रय के उपरांत भी किनके साथ सम्बद्ध किया गया, ये भी संचिका उपलब्ध नहीं है। लेखा परीक्षा में आगे पाया गया कि APR ऑटोमोबाइल, गया द्वारा गाड़ियों के मूल्य हेतु दो कोटेशन जिसमे कोटेशन संख्या-7835 स्कार्पियो N-Z6-D-MT-7 एवं कोटेशन संख्या-7836 स्कार्पियो N-28-L-D-MT-7 क्रमशः रु० 19,53,459/- एवं रु० 24,45,440/- समर्पित किया गया था, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कोटेशन की प्राप्ति हेतु कोई भी पत्र लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह प्रतीत हो की उक्त एजेंसी द्वारा मूल्य का कोटेशन विश्वविद्यालय द्वारा मांग करने के पश्चात् उपलब्ध कराया गया था। गाड़ियों के क्रय से पूर्व यह भी सुनश्चित नहीं किया गया था कि जिन पदाधिकारियों के लिए गाड़ी क्रय किया जा रहा है उनके पास उपलब्ध गाडी की स्थिति क्या थी एवं नयी गाड़ी क्रय के पश्चात् पूर्व के गाड़ियों का क्या उपयोग किया जा रहा था? दिनांक-10.11.23 को कोटेशन के आधार पर दिनांक-10.11.23 को ही चेक के माध्यम से भुगतान किया गया, परन्तु गाड़ी क्रय से सम्बंधित मूल अभिश्रव न तो किसी संचिका में संलग्न पाया गया एवं न ही लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया। साथ ही स्कार्पियो गाड़ी ही क्रय किये जाने का निर्णय एवं आधार भी न तो संचिका में उपलब्ध था एवं न ही लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार बिना निविदा निष्पादन के बिना GeM पर अधिप्राप्ति के बिना गाड़ी के specification निर्धारण के स्कार्पियो का क्रय करना, बिना कोटेशन के मांग के एजेंसी द्वारा दिए गए कोटेशन पर ही गाड़ी के क्रय करने के विश्वविद्यालय में गाड़ियों के सूची का संधारण नहीं करने के एवं गाड़ी क्रय करने के पश्चात् भी अभिश्रव के अनुपलब्ध रहने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाए एवं इस प्रकार अनियमित रूप से रु० 43,98,899/- के क्रय का क्या औचित्य है, से भी लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाए।●

डॉ. बिन्देश्वर प्रसाद गुप्ता की आपबीती घटना

कार्तिक पूर्णिमा के दिन भयंकर हादसा होने से बचा था पटना

● सोनू यादव

विगत् 5 नवम्बर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दोपहर 1 बजे तीन-चार सौ से अधिक लोग गंगा पार स्नान करने के लिए गए थे, किन्तु उन लोगों को लाने के लिए कोई नाव नहीं था। मल्हारों ने नाव चलने के पहले ही, नाव पर बिठाने के बाद आने-जाने का किराया वसूली लिया था और कहा था कि लौटते वक्त किसी भी नाव से लौट सकते हैं। कोई नाव वाला किराया नहीं माँगेगा। लगभग 12:00 बजे के बाद मल्हारों ने सभी लोगों को गंगा पार पहुँचाने के बाद घाट लौट आया। फिर उन लोगों को लाने के लिए कोई नहीं गया । इधर गंगा के पार के लोगों ने स्नान करने के बाद 2 घंटे से नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि लौटा जा सके। वैसे भी वे सभी निश्चिंत थे कि कुछ देर के बाद नाव आ जाएगी। तीन-साढ़े तीन बजने जा रहे थे और शाम होती जा रही देखकर , कोई भयावह दुर्घटना न हो , अंततः उन्हीं में से एक स्वतंत्र पत्रकार (फ्री लांसर) डा. बिन्देश्वर प्रसाद गुप्ता ने इमरजेंसी पुलिस आपदा मो.112 को फोन लगा कर बताया कि, दरभंगा हाउस, पटना स्थित कालीघाट पर कोई पुलिस नहीं है। मल्लाहों ने गंगा के उस पार हम सभी को लाकर छोड़ दिया है और 2-3 घंटे से कोई नाव घाट से नहीं आई है, जिस कारण सभी लोग नाव आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मैंने प्रेशर देकर कहा कि, पुलिस भेज कर एक नहीं बल्कि तीन-चार नावों को भिजवाएं। यदि एक नाव भी आती है, तो पूरी भीड़ एक नाव पर चढ़ने को उतावली हो जाएगी और बीच गंगा में नाव डूब सकती है, जिस तरह पिछली बार भी काफी यात्रियों से भरी नाव बीच गंगा में डूब गई थी। शाम होने जा रही है, कुछ भी हादसा हो सकता है। जल्दी कीजिए...! डी.एम. साहब को सूचना दीजिए, ताकि अतिशीघ्र कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि वह डी. एम. को फोन नहीं कर सकती है। आप ही फोन डी.एम. के पास कीजिए। उन्होंने मेरे माँगने पर डीएम साहब का फोन नंबर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वह घाट किस थाना के अंतर्गत पड़ता है। मैंने पीरबहोर, कदमकुँआ, थाना बताया।

डॉ० त्याग राजन
जिलाधिकारी, पटना

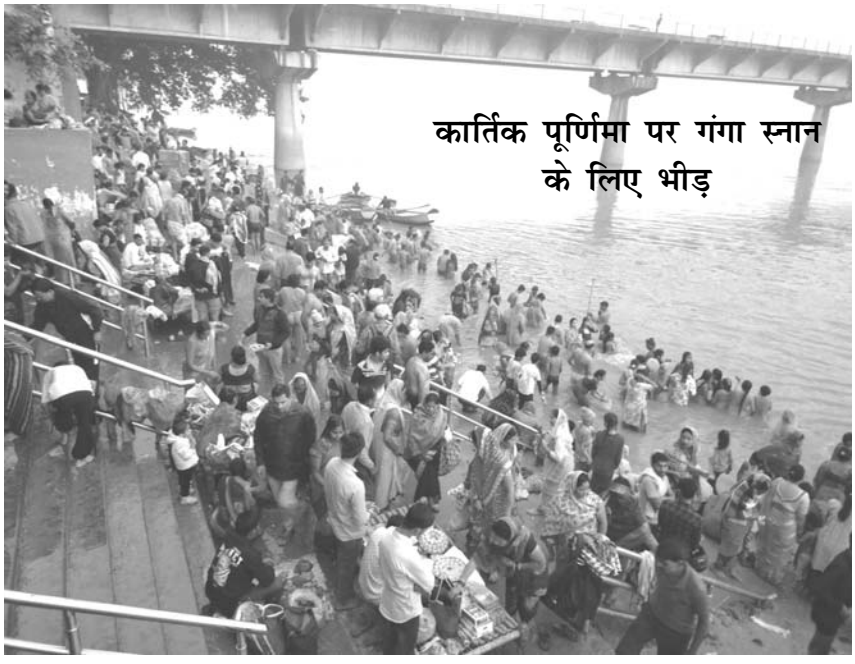

कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए भीड़

कुछ देर पश्चात् पीरबहोर थाना ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझसे सारी बातें पूछी और मैंने बताया तो उन्होंने तुरंत आने की बात कही। इसी बीच मैंने डीएम ऑफिस में फोन किया तो वहाँ से एक कर्मचारी ने बताया कि डीएम साहब मीटिंग में है। उनसे बात नहीं कराई जा सकती है। मैंने स्वयं डी.एम. साहब को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि, मैं डी.एम. हूँ। उनके द्वारा पूछने पर मैंने वस्तुस्थिति से अवगत कराया। मैंने बताया कि एक काफी भयंकर अप्रिय घटना/हादसा होने जा रही है। मैं स्वतंत्र पत्रकार बिन्देश्वर प्रसाद गुप्ता हूँ। गंगा के उस पार हूँ। फिर उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आप गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप गंगा के उस पार क्यों गए, स्नान करने के लिए? मैंने बताया कि, आज कार्तिक पूर्णिमा है। सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ। मेरे जाने से पहले हजारों लोग सुबह से आ जा रहे हैं और अभी भी इस समय चार-पाँच सौ आदमी से अधिक लोग गये हुये हैं। इस बार काफी गंदा कूड़ा-करकट से भरा हुआ नदी का पानी है, स्नान करने योग्य नहीं है। इसलिए लोग उस पार जाते हैं। घाट पर पुलिस प्रशासन का कोई आदमी नहीं था, जो नाव पर जाने से यात्रियों को रोक सके। यात्रियों को जाने ही नहीं देना चाहिए था। इसके लिए घाट पर

डॉ० बिन्देश्वर प्रसाद गुप्ता

कूड़ा-कड़कट, कीचड़ को हटाकर सफाई करना चाहिए था।

डी.एम. साहब ने गुस्सा कर कहा-तो क्या आप मुझसे सफाई करने के लिए कह रहे हैं? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप निगम से करवा सकते हैं न? गंगा की सफाई, घाट की सफाई नहीं हो सकती है क्या? तभी, स्नान करने के लिए गंगा पार जाने के लिए लोगों को रोकी जा सकेगी। मैने कहना चाहा कि दिल्ली में यमुना नदी की सफाई हो सकती है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सफाई करवा सकती है, तो फिर पटना में क्यों नहीं? किन्तु विषयांतर होते देखकर, डीएम साहब ने पूछा-आप क्या चाहते हैं? मैंने जवाब दिया कि बस यथाशीघ्र तीन-चार नावों को पुलिस से कहकर कालीघाट से भिजवा देने की कृपा करें। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे। एक-दो नाव, आगे पीछे नहीं भेजेंगे बल्कि एक साथ तीन-चार नावों को भिजवाएंगे, जिसे दूर से ही देखकर, लोगों की पूरी भीड़ एक या दोनों ही, नावों पर नहीं जाकर भरेगी और बीच गंगा नदी में जाकर नहीं डूबेगी। मल्हार को निर्देश दिलवा देंगे कि क्षमता से अधिक लोगों को नहीं नाव पर लेंगे। अन्यथा नाव डूबने की भयंकर घटना हो सकती है।

डीएम साहब ने ठीक है। मैं देखता हूँ...कुछ करता हूँ...कह कर मोबाइल बंद कर दिया। इसी बीच, पीरबहोर थाना से एक पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया। उसने कहा कि मैं कालीघाट पर आ गया हूँ और नाव भेजने की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैंने पूछा-आपका नाम क्या है? तब उन्होंने कहा-मनोज कुमार। मैंने कहा कि, एक नाव या दो नाव नहीं भेजेंगे। एक साथ, तीन-चार नाव भेजेंगे। इससे सभी लोग दूर से ही देख सकेंगे और चारों नावों में भीड़ बँट जाएगी। इस कारण नाव में क्षमता से अधिक भीड़ नहीं जा पायेगी तथा नदी में लोगों की भीड़ सहित नाव डूबने से बच जाएगी और कोई दुर्घटना नहीं हो सकेगी। हाँ, आपने ठीक कहा। मैं तीन चार-नावों की व्यवस्था कर रहा हूँ और एक साथ भेजूँगा, फिर मोबाइल बंद कर दी। अब चार-साढ़े चार बजने जा रहे थे। मैंने मौखिक रूप से भी आसपास लोगों को बता दिया और कहा कि आप लोग भी अपने-अपने मोबाइल से फोन कीजिए ताकि पुलिस पर प्रेशर पड़ेगा और शीघ्र ही कार्रवाई होगी।

कुछ देर के बाद तीन खाली नावें एक साथ कालीघाट से हमलोगों की तरफ आती हुई दिखाई पड़ने लगी। पूरी भीड़ नावों को देख कर खुशी से नाचने लगी। जैसे ही तीनों नाव निकट में आई, लोग दौड़ पड़े। भीड़ पानी में कूद पड़ी। सभी लोग नाव में पहले जाना चाह रहे थे ताकि छूट न जाए। देखते-देखते तीनों नाव पूरी तरह भर गई। सिर्फ पत्नी और बेटी सहित मैं तीन लोग और मेरे साथ दो सहयात्री, जयश्री तथा उसकी बूढ़ी माँ बच गये थे। पूरी भीड़ की क्षमता चार-पाँच नावों की थी। हम पाँचों व्यक्तियों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन तीनों नावों में से किसी पर भी चढ़ें, क्योंकि सभी तीनों नाव खचाखच भरी हुई दिखाई पड़ रही थी। हालांकि चौथी नाव आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही थी, फिर भी मैंने चीख कर लोगों से कहा, चौथी नाव आ रही है, कुछ लोग उतर जायें। किन्तु, एक बार नाव पर चढ़ जाने पर कौन उतरता है? और भीड़ में से कुछ लोग हम सभी को डरा हुआ देख, हमारी नादानी समझ कर हँस रहे थें और वे सभी उन्हीं की नाव पर सवार होने के लिए बुला रहे थें। मैं झेंप गया था। इसी बीच, दूर से चौथी नाव भी सामने आती हुई दिखाई पड़ी।

पुलिस अधिकारी का फोन आया-मैंने चौथी नाव भी भेज दी है। जी! शुक्रिया। किन्तु, भीड़ में से कुछ लोगों का चीखना जारी था। आ जाइये। जल्दी आइये। नाव खुल रही है। कोई भी, चौथी नाव पर जाने को तैयार नहीं था। फिर, मैंने मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते हुए सपरिवार तथा मेरे साथ दो यात्री सामने स्थित दूसरी नाव पर सवार हो गयें। और अब देर से भेजी गई चौथी खाली नाव, हमलोगों को ले जाने के लिए सामने से आती हुई दिखाई पड़ी। अबतक, हम सभी लोग इन तीनों नावों में भर कर सवार हो गये थें।

किसी व्यक्ति ने भी नहीं चाहा कि सुरक्षा की दृष्टि से भीड़ से भरी हुई इन तीनों नावों में से दस-दस, बीस-बीस व्यक्ति भी उतर कर, नावों को हल्का करने के लिए खाली कर दें और इस चौथी नाव में चले जायें ताकि भीड़ से नाव डूबने जैसी कोई अनहोनी भयंकर दुर्घटना नहीं हो सके। जब मैंने इस नाव पर सवार उपस्थित लोगों को बताया कि इस नाव पर सवार होकर आप जो खुश हो रहे है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये तीनों नाव अपने आप हम लोगों को ले जाने के लिए आयी हैं? नहीं। दो-तीन घंटे से एक भी नाव हम सभी को ले जाने के लिए नहीं आई, जबकि इन मल्हारों को मालूम था कि उन्होंने हम सभी को लाकर यहाँ छोड़ा है। आप सभी रील, वीडियों बनाने में मस्त थें। यदि मैं पुलिस लाईन आपदा को फोन नहीं करता, पीरबहोर थाना को फोन कर यहाँ के बारे में नहीं बतलाता, डीएम साहब को फोनकर वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराता, उनसे एक साथ तीन-चार नावों को भेजने के लिए नहीं अनुरोध करता और वे तत्काल आवश्यक कार्रवाई नहीं किये होते, मेरे कहने के अनुसार पीरबहोर थाना से आये पुलिस इंस्पेक्टर घाट पर आकर मेरे कहने के अनुसार तीन चार नावों को तुरंत भेजने के लिए नहीं कार्रवाई करते तो, ये तीनों नाव नहीं आई होती और अभी तक यहीं पड़े होते। इतना सुनना था कि नाव पर सभी युवक, खुशी से मुझे भैया की जय, भैया की जय से जय जयकार करने लगे। सच पूछिये, कसम खाकर मैं कहता हूँ, मैंने इस पल की कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी जय जयकार होगी। मैं उनके जयजयकार से अभिभूत हो गया।

अब ईश्वर कृपा से हम सभी की क्षमता से अधिक संख्या में भरी तीनों नाव प्रस्थान होकर अपने गंतव्य की ओर चली तथा पटना कालेज घाट के पास आ रूकी। यहाँ पहुँचते ही, पीरबहोर थाना के पुलिस मनोज कुमार इंस्पेक्टर हाथ में वीडियोग्राफी लेते हुए मेरे साथ आयी सहयात्री जयश्री से विस्तार से प्रश्न पूछा और वस्तुस्थिति की जानकारी ली। फिर मुझसे पूछा गया कि आपके बुलाने पर पुलिस तुरंत आई कि नहीं? कार्रवाई हुई कि नहीं? कितनी देर बाद आई? मैंने कहा-आधे घंटे के बाद तुरंत कार्रवाई की गई, जिसके लिए पीरबहोर थाने की पुलिस को बधाई। आपने मेरी सलाह को संज्ञान लिया तथा एक साथ तीन नावों को ही भेजा हालांकि एक साथ तीन के स्थान पर चार नावों को भेजना चाहिए था। आगे से किसी पर्व-त्योहार में उपर्युक्त इन सारी बातों को अवश्य ध्यान में रखकर लोकहित में, लोगों की सुरक्षा में अपना योगदान प्रदान करेंगे।

हमलोग सभी सुरक्षित लौट चुके थे। ऐसा महसूस हुआ कि सभी लोगो को सुरक्षित

लाने के लिए ही ईश्वर ने मुझे गंगा के उस पार स्नान करने के लिए भेजा था अन्यथा पिछले वर्ष मैंने सपरिवार गंगा नदी के इसी पार काली घाट में स्नान किया था, गंगा के उस पार नहीं गया था।

उल्लेखनीय है कि :-

☞ यदि मैं उस पार नाव से नहीं गया होता, तो उस भीड़ में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो मेरे जैसा ही पुलिस को, डी.एम. को सूचना देकर एक साथ तीन - चार नावों को भेजने की मानसिकता का उपयोग कर एक बड़ी हादसा को होने से रोक पाता।

☞ संभवत: ऐसा ही होता कि यदि एक नाव या दो नावें देर संध्याकाल में यात्रियों को लाने के लिए आती भी तो सैकड़ो लोगों की भीड़ एक साथ नावों पर पहले जाने के लिए दौड़ पड़ती, भगदड़ मच जाती, कितने लोग चिपा जाते, घायल होते या मरते। क्षमता से अधिक भरी हुई एक नाव या दोनों नावों में सवार भारी भीड़, बीच नदी में अनियंत्रित होने से, नाव डूबने से कितने लोगों की जान चली जाती, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, कल्पना करना भी दिल को दहला देती है।

☞ जैसा कि पिछले वर्षों में, क्षमता से अधिक यात्रियों का नाव में सवार होने से बीच नदी में नाव डूब गयी थी और कई लोगों/सभी लोगों की जान चली गई थी। यह दुर्घटना दूरदर्शन पर देखने को मिली थी और समाचार-पत्रों में भी काफी प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। शायद इसी तरह की खबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को टी. वी. पर सुनने और देखने को मिलती।

☞ छ: तारीख को हुए मतदान के सिर्फ एक दिन पहले विपक्ष इस संभावित हादसा को आड़े लेने में बिल्कुल नहीं हिचकता और इसे सुनियोजित बतलाता, फिर आगे क्या होता इसकी कल्पना भी भयावह ही होता, इसमें दो मत नहीं।

☞ यह गौरतलब बात है कि कार्तिक पूर्णिमा जैसी आस्था का महत्वपूर्ण पर्व जिसमें गाँवों-गाँवों से काफी संख्या में पुरुष-महिलाएं, बच्चे गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। हर घाट में काफी बड़ी भीड़ होती है। हर वर्ष लोगों को गंगा के उस पार ले जाने के लिए दिन भर, लगातार नावें चला करती हैं। इस बार भी सुबह से ही नावें चल रही थी। मैं स्वयं सपरिवार 1 बजे मल्हार के बुलाने पर जाने के लिए तैयार यात्री से भरी नाव में सवार होकर घाट के उस पार गया। मल्हार ने जबरदस्ती आने-जाने दोनों तरफ का किराया नाव पर सवार सभी यात्रियों से ले लिया और कहा कि उधर से कोई भी नाव आपको ले आएगा।

☞ तब सभी नावें वहाँ से (गंगा पार) छोड़ कर काली घाट क्यों चली गयी और फिर हम सभी सैंकड़ों लोगों को ले जाने के लिये क्यों नहीं आया? यह जानबूझकर कर या किसी नियोजित साजिश के तहत ऐसा किया गया।

☞ उस समय घाट पर पुलिस नहीं थी, अत:, पीरबहोर थाना से मोबाइल से मनोज कुमार एक पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि, ठीक है हम आपके द्वारा बताये गये घाट पर आ रहे हैं। घाट पर आने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि अभी मैं घाट पर आ गया हूँ। मैं थोड़ी देर में नाव को भिजवा रहा हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय घाट पर पुलिस नहीं थी। यदि पुलिस नहीं आती, तो नाव वहाँ से नहीं चलती। फिर हमलोगों को लाने के लिए कोई नाव नहीं आती।

☞ घाट पर मल्लाह को मालूम था उसने दो-तीन घंटे पहले गंगा पार जाकर यात्रियों को छोड़ा है।

☞ अत:, ऐसी भी होने की संभावना बनती है, यदि मैं अपनी पत्रकारिता की बुद्धि नहीं लगाई होती और सभी लोगों की तरह मैं भी पुलिस से संपर्क नहीं किया होता, 5-6 बजे संध्या को ही अंधेरा छा जाती, संयोग से एक नाव आयी होती, मल्हार के द्वारा लाख कहे जाने पर कि पारी-पारी से लोगों को ले जायेंगे। भीड़ को धैर्य, संयम नहीं होता। सभी इसी नाव पर चढ़ जाते, संभवत: मैं भी सपरिवार सवार हुए होते, नाव ओवरलोडेड हो जाता, क्षमता से अधिक लोग सवार होते, तो निश्चित था कि नाव गंगा में डूब गई होती।

☞ तो आज कुछ दूसरा ही नजारा होता/देखने को मिलता। हम सभी सैकड़ों की भीड़ सहित जीवित नहीं रहते। पूरा पटना में कोहराम मचा होता और इन पंक्तियों को लिखने के लिए मैं भी जीवित नहीं रहता।

☞ मुझे ईश्वर परअटूट विश्वास है। मेरा मानना है कि सभी कुछ ईश्वर करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। उन्होंने ही मेरी बुद्धि इस प्रकार कर/दे दी कि मैंने पुलिस कंट्रोल तथा डी.एम. को निर्भीकतापूर्वक सूचित कर पुलिस बुलायी और मेरे कहने पर पुलिस ने तीन नावों को भेज कर हम सभी सैकड़ों की भीड़ सहित अपने परिवार संग नदी में डूब कर दुनिया को अलविदा कहने से बच गए। आज आपके सम्मुख जीवित हूँ। आपके साथ अपने सुख-दुख साझा करने के लिए।

☞ ठीक ही कहा गया है-जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय।

अंतत:, मेरे कहने का अभिप्राय है कि अगली बार से प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृति नहीं हो। ●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

न्याय प्रणाली में न्याय समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति तक पहुँचना बेहद जरूरी : मुख्य न्यायाधीश

● **श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव**

न्याय प्रणाली में कमजोर एवं असहाय लोगों के प्रति सहानुभूति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से एक न्यायपूर्ण समाज और अन्यायपूर्ण समाज में फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्याय कहा कि न्याय उन लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

बताते चले कि मुख्य न्यायाधीश ने पटना के चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में युवा और ऊर्जावान वकीलों को याद दिलाया कि अपने पेशा में मेहनत और जोश होना जरूरी है, लेकिन इसके कारण संवेदनहीन नहीं होना है जिससे नैतिक मूल्यों एवं भावनाओं को ठेस पहुँचे। उन्होंने कहा कि कई युवा वकील मानते हैं कि सफलता के लिए कार्य, नियमों और उम्मीदों के प्रति पूरी तरह समर्पित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए यह जोश जरूरी है लेकिन इससे मन की संवेदनशीलता नहीं मिटनी चाहिए। अगर कानून आपके जीवन के हर हिस्से पर हावी हो है तो आप उस सहानुभूति और न्याय के लिए जरूरी समझ खो सकते हैं, जो सही न्याय के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी कानून प्रणाली में यही सहानुभूति एक न्यायपूर्ण समाज को अन्यायपूर्ण समाज से अलग करती है। सीजेआई ने युवा

वकीलों से कहा कि जब आप इस विश्वविद्यालय से विदा होंगे तो याद रखें कि कानून सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, जो इसे वहन कर सकते हैं बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप अपनी क्षमताओं का उपयोग आम लोगों के लाभ के लिए करें। उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि क्या आप कानून को बेहतर बनाने और न्याय की दिशा उन समुदायों की ओर मोड़ने के लिए तैयार हैं, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरून है यानि समाज के शोषित, दबे-कुचले एवं कमजोर लोगों के लिए। सीजेआई ने बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास की सराहना करते हुए कहा कि यह भूमि तार्किक विचारकों और महान चिंतकों की भूमि है और लंबे समय से नीति, तर्क व न्याय का संगम रही है।

बिहार राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आये सीजेआई ने इससे पहले पटना हाईकोर्ट परिसर में बुनियादी ढांचो से जुड़ी सात परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का विकास बेहद जरूरी है ताकि बढ़ती आबादी, बढ़ते मुकदमों और जटिल होते विवादों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सात परियोजनाओं में एक एडीआर भवन एवं सभागार, एक आईटी भवन, एक प्रशासनिक भवन, बहु-स्तरीय कार पार्किंग, एक अस्पताल, पटना उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक आवासीय भवन तथा महाधिवक्ता कार्यालय का एक भवन शामिल है। सीजेआई ने अपने संबोधन में कहा कि पटना हाईकोर्ट के प्रशासनिक ब्लॉक, आईटी ब्लॉक और अन्य सुविधाओं के लिए शिलान्यास अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इस अवसर का बिहार में और भी गहरा महत्व है, जो भारत की सभ्यतागत स्मृति में एक विशिष्ट स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली के दक्षता विकास का अभिप्राय बढ़ती आबादी के जरूरतमंद लोगों तक पहुँच से है।●